



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 27 मार्च, 1993/ 6 चैत्र, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जनवरी, 1993

सं० एल० आर० (राजभाषा) बी (16) 15/92.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक-उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1968 (1969 का 3)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968

(1969 का अधिनियम संख्यांक 3)

22-2-1969

19-7-1969

(31-8-1991 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में सहकारी सोसाइटीयों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।
- (3) यह ऐसी तारीख को वृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :—
 - (1) “उपविधि” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई उप-विधि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उप-विधि का रजिस्ट्रीकृत संशोधन है;
 - (1-अ) “क्लैक्टर” से जिले का क्लैक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जिलाधीश और इस अधिनियम के अधीन क्लैक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई अन्य अधिकारी है;
 - (2) “नमिति” से अभिप्रेत है सहकारी सोसाइटी का शासकीय निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे सोसाइटी का प्रबन्ध सौंपा गया हो;
 - (3) “सहकारी सोसाइटी” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है;
 - (4) “अपरसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके सदस्यों का इसके परिसमापन की दशा में सोसाइटी की अस्तित्वों में किसी कमी को पूरा करने के लिए संयुक्तता और पृथक्ता अभिदाय करने के प्रयोजन के लिए दायित्व अपरसीमित है;
 - (5) “परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी” से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस राशि तक, यदि कोई हो, परिसीमित है, जो उन द्वारा क्रमशः धारित शयरों पर अंतर्दत्त है या उस राशि तक जिसका सोसाइटी के परिसमापन की दशा में, उसकी अस्तित्वों के प्रति क्रमशः व अभिदाय करने का जिम्मा लेते हैं;
 - (6) “सहकारी वर्ष” से 1 जुलाई से 30 जून तक प्रारम्भ होने वाला वर्ष या सरकार द्वारा सहकारी सोसाइटी के लेखे रखने के लिए विहित वर्ष अभिप्रेत है;

- (6-अ) "निक्षेप बीमा निगम" से निक्षेप बीमा और उधार गारंटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा और उधार गारंटी निगम अभिप्रेत है;
- (7) "विवाद" से अभिप्रेत है, कोई मामला जो सिविल मुकदमेंवाजी का विषय बन सकता हो और सहकारी सोसाइटी को देना या उपद्रा देना किसी राशि के बारे में दावा इसके अन्तर्गत है, चाहे ऐसा दावा स्वीकार किया जाएगा नहीं;
- (8) "कुटुम्ब" से पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं;
- (9) "संघ सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके कम से कम 3/4 सदस्य सोसाइटियां हैं;
- (10) "सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए जाने वाले आवेदन में सम्मिलित होता है और ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार किए गए रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके अन्तर्गत नाममात्र और सहयुक्त सदस्य भी हैं;
- (11) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, प्रभु, उप-प्रभु, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव, इसके अन्तर्गत प्रबन्धक, समिति का सदस्य, कोषपाल, सहायक, प्रशासक और सहकारी सोसाइटी के काम-काज के सम्बन्ध में नियमों या उप-नियमों के अधीन निर्देश देने के लिए सशक्त कोई अन्य व्यक्ति है;
- (12) "रजिस्ट्रार से धारा 3 के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति है जिस पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की सभी या कोई शक्तियां अथवा कर्तव्य प्रदत्त या अधिरोपित किए गए हों;
- (12-अ) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन गठित रिजर्व बैंक अभिप्रेत हैं;
- (13) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए गए समझे जाने वाले नियम अभिप्रेत है;
- (14) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (15) "सोसाइटी" या "रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (16) "राज्य सरकार" या "सरकार" से जब तक अन्यथा अभिव्यक्ति न हो, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (17) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (17-अ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है; और
- (18) "वित्तीय बैंक" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके उद्देश्यों के अन्तर्गत अन्य सहकारी सोसाइटियों को उधार देने के लिए निधियों का सृजन भी है।

अध्याय-2

सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण

- 3- (1) राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उसकी सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन साक्षरता व विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार को सभी या कोई भी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उप-धारा (2) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रार के सामान्य मार्ग-दर्शन, अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन करेगा।

सोसाइटीयां
जो रजिस्ट्री-
कृत की जा
सकेंगी।

4. इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका उद्देश्य सहकारी मित्रता के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक हितों की अभिवृद्धि करना है अथवा उस सहकारी सोसाइटी के कार्यों को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित कोई सोसाइटी जिसके अन्तर्गत किसी विद्यमान सोसाइटी के विनिश्चय अथवा विद्यमान सोसाइटीयों के सम्मेलन द्वारा गठित सोसाइटी भी है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी।

परिसीमित
या अपरि-
सीमित
दायित्व
सहित रजि-
स्ट्रीकृत।

5. (1) कोई सहकारी सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी :

परन्तु—

- (i) ऐसी सहकारी सोसाइटी का, जिसकी सदस्य कोई सहकारी सोसाइटी है, दायित्व परिसीमित होगा; और
- (ii) कोई भी सहकारी सोसाइटी, जिसके उद्देश्यों में सदस्यों को कृपण देने के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य भी सम्मिलित हों, अपरिसीमित दायित्व वाली सोसाइटी के रूप में रजिस्टर नहीं की जाएगी।

(2) "परिसीमित" या किसी भारतीय भाषा में इसका समतुल्य शब्द, इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी के नाम का अन्तिम शब्द होगा।

शेयर धारण
करने पर
निर्बन्धन।

6. किसी भी सहकारी सोसाइटी में, सरकार या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य, —

- (क) सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के पांचवें भाग से अनाधिक ऐसा भाग पारित नहीं करेगा जो विहित किया जाए; या
- (ख) ऐसी सोसाइटी के शेयरों में दस हजार रुपये से अधिक कोई हित नहीं रखेगा या दावा नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी सहकारी सोसाइटी के सम्बन्ध में, यथास्थिति, शेयर पूंजी के पांचवें भाग से उच्चतर अधिकतम या दस हजार रुपये से उच्चतर राशि विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

रजिस्ट्री-
करण के लिए
आवेदन।

7. (1) सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाए, रजिस्ट्रार को किया जाएगा और आवेदक इसे सोसाइटी के बारे में ऐसी सारी सूचनाएं देगा जो उस द्वारा अपेक्षित हों।

(2) ऐसी प्रत्येक आवेदन, निम्नलिखित के अनुरूप होगा :—

- (क) आवेदन के साथ सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों की तीन प्रतियां संलग्न की जाएंगी ;
- (ख) जहां सभी आवेदक व्यक्ति हों, वहां आवेदकों की संख्या दस से कम नहीं होगी और दस ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक, भिन्न कुटुम्ब का सदस्य होगा तथा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा (11) के अधीन संविदा करने में सक्षम होगा और जहां सभी आवेदक व्यक्ति नहीं हैं वहां ऐसे आवेदकों की संख्या पांच से कम नहीं होगी ;
- (ग) आवेदकों में से प्रत्येक जो व्यक्ति है 18 वर्ष की आयु से ऊपर का होगा ; और
- (घ) जहां सहकारी सोसाइटी के उद्देश्य में इसके सदस्यों को उधार देने के लिए निधियों का सृजन करना सम्मिलित है और जहां सभी आवेदक व्यक्ति हैं वहां आवेदक उसी कस्बे या गांव या गांव के समूह के रहने वाले होंगे या उनका सामान्य हित होगा या उनका एक ही व्यवसाय होगा ।

(3) आवेदक निम्न द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा :—

- (क) ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई भी सहकारी सोसाइटी नहीं है, उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) की अपेक्षाओं के अनुसार अहित सभी व्यक्तियों द्वारा ; और
- (ख) ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई सहकारी सोसाइटी है, ऐसी प्रत्येक सोसाइटी की और ऐसे सम्युक्त रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, और जहां सोसाइटी के सभी सदस्य सोसाइटियों नहीं हैं, वहां अन्य सभी सदस्यों द्वारा ।

8. (1) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि —

रजिस्ट्रीकरण

- (क) आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार है ;
- (ख) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य धारा 4 के अनुसार हैं ;
- (ग) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से असंगत नहीं हैं ;
- (घ) प्रस्तावित उप-विधियां इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं, और
- (ङ) प्रस्तावित सोसाइटी की सफलता की युक्तियुक्त संभावना है ; तो वह सोसाइटी और उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए, आवेदन का रजिस्ट्रार द्वारा निपटान उसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) यदि रजिस्ट्रार, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन को निपटाने में असफल रहता है तो आवेदक सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी ।

(4) जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को रजिस्टर करने से इन्कार करे तो वह इन्कारी आदेश उसके कारणों सहित, ऐसे आवेदकों को संसूचित करेगा जो विहित किए जाएं ।

9. जहां कोई सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर की जाती है या धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाती है तो रजिस्ट्रार उस द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा जो इस

रजिस्ट्रीकरण
साक्ष्य ।

बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें उल्लिखित सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन सम्पूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकृत है जब तक कि यह साबित नहीं किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

सोसाइटीयों
का निर्गमित
निकाय होना।

10. किसी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण, उसे उस नाम से निर्गमित निकाय बना देगा जिस नाम से वह रजिस्ट्रीकृत है, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे सम्पत्ति धारण करने, संविदा करने बौद्ध और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करने और प्रतिवाद करने और उन प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक कार्य करने की शक्ति होगी, जिसके लिए उसका गठन किया गया है।

सहकारी
सोसाइटी की
उपविधियों
का संशोधन।

11. (1) सहकारी सोसाइटी की किसी उपविधि का कोई संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि किसी सधारण बैठक के संकल्प द्वारा अनुमोदित न हो और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो जिसे प्रयोजन के लिए संशोधन की तीन प्रतियाँ रजिस्ट्रार को भेजी जाएंगी जैसा विहित हो।

(2) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन, —

- (i) इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के प्रतिकूल नहीं है ;
 - (ii) सहकारी सिद्धांतों से असंगत नहीं है ;
 - (iii) सोसाइटी के सदस्यों के आर्थिक या सामाजिक हितों की अभिवृद्धि करेगी ;
 - (iv) सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से असंगत नहीं है ;
- तो वह संशोधन को रजिस्टर कर सकेगा।

(3) जब रजिस्ट्रार किसी संशोधन को रजिस्टर करता है तो वह रजिस्ट्रीकृत संशोधन की एक प्रति, उस द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सहित, सोसाइटी को भेजेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्पूर्ण रूप से रजिस्टर किया गया है।

(4) जहां रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों के संशोधन को रजिस्टर करने से इन्कार करता है वह इन्कार आदेश, उसके कारणों सहित, सोसाइटी को संसूचित करेगा।

(5) कोई संशोधन जो रजिस्ट्रार द्वारा इसकी प्राप्ति के 90 दिन के भीतर नहीं निपटाया जाता है तो वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा और ऐसे संशोधन पर इन धारा की उप-धारा (3) के उपबन्ध लागू होंगे।

(6) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन, जब तक कि इसका किसी विशिष्ट दिन को प्रवृत्त होना अभिव्यक्त न हो, उस दिन प्रवृत्त होगा जिसे दिन इस रजिस्टर किया जाता है।

उपविधियों
में संशोधन
करने का
निर्देश देने
की रजि-
स्ट्रार की
शक्ति।

11-अ. (1) यदि रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी की उप-विधियों का संशोधन लोक हित में या सोसाइटी के हित में अथवा सहकारी आन्दोलन के हित में, आवश्यक या वांछनीय है तो वह लिखित रूप में सोसाइटी से ऐसे समय के भीतर जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षित संशोधन करने की आकांक्षा कर सकेगा।

(2) यदि सोसाइटी विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे संशोधन को रजिस्टर कर सकेगा और सोसाइटी को उस द्वारा ऐसे संशोधन की प्रमाणित प्रति जारी करेगा। ऐसे संशोधन के उपर्युक्त रीति से रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उप-विधियाँ सम्पूर्ण रूप से संशोधित

समझी जाएगी सोसाइटी और यथा संशोधित उपविधियां सोसाइटी और उसके सदस्यों पर अबाधक रहेंगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई प्रमाणित प्रति इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि संशोधन सम्यक् रूप से रजिस्टर किया गया है।

12. (1) कोई सहकारी सोसाइटी, अपनी उप-विधियों में संशोधन द्वारा, अपना नाम परिवर्तित कर सकेगी।

(2) जहां कोई सहकारी सोसाइटी अपना नाम परिवर्तित करती है रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियों के रजिस्टर में पहले नाम के स्थान पर नए नाम को दर्ज करेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन करेगा।

नाम का परिवर्तन और उसका प्रभाव।

(3) सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन, सहकारी सोसाइटी के या उसके सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों में से किसी अधिकार या बाधता पर प्रभाव नहीं डालेगा, और कोई भी निलम्बित विधिक कार्यवाहियां सोसाइटी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध, उसके नए नाम के अधीन चालू रखी जा सकेंगी।

13. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अधीन रहते हुए, सहकारी सोसाइटी अपनी उप-विधियों में संशोधन द्वारा दायित्व के स्वरूप या परिमाण में परिवर्तन कर सकेगी।

दायित्व परिवर्तन।

(2) जब सहकारी सोसाइटी ने अपने दायित्व या परिमाण में परिवर्तन करने का कोई संकल्प पारित कर दिया हो तो वह अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को उसका लिखित नोटिस देगी और किसी उपविधि या संविदा के प्रतिकूल होते हुए भी किसी सदस्य या लेनदार को, उस पर नोटिस की तारीख की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर, यथा स्थिति, अपने शेयरों, निक्षेपों या ऋणों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा।

(3) कोई सदस्य या लेनदार जो उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने परिवर्तन की अनुमति दे दी है।

(4) उसके दायित्व के स्वरूप या परिमाण में परिवर्तन करने वाला कोई किसी सहकारी सोसाइटी की उप-विधि का कोई संशोधन, तब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा या प्रभावी नहीं होगा जब तक कि या तो,—

(क) उसके सम्बन्ध में सभी सदस्यों और लेनदारों की अनुमति अभिप्राय नहीं कर ली जाती है, या

(ख) ऐसे सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों का पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया जाता है, जिन्होंने उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट विकल्प का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोग किया है।

14. (1) कोई सहकारी सोसाइटी, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से और सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन चौथाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा,—

(क) अपनी आस्तियों और दायित्वों को पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य सोसाइटी को अन्तर्गत कर सकेगी ;

(ख) स्वयं को दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजित कर सकेगी और ऐसी ही नई सोसाइटियां बना सकेगी ;

सोसायटियों का समा-मेलन, आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण, संपरिवर्तन और विभाजन।

(ग) स्वयं को सोसाइटी के किसी अन्य वर्ग में संपरिवर्तित कर सकगी और ऐसे ही नए वर्ग की सोसाइटियाँ बना सकेंगी :

परन्तु बीमाकृत बैंक की दशा में, इस उपधारा के अधीन कोई भी संकल्प भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के पारित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई दो या उससे अधिक सहकारी सोसाइटियाँ, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी प्रत्येक सोसाइटी की किसी विशेष साधारण बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वयं ही समामेलित कर सकेंगी और नई सोसाइटी बना सकेंगी।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन सहकारी सोसाइटी का संकल्प, यथास्थिति, अन्तरण, विभाजन संपरिवर्तन अथवा समामेलन की सभी विधिष्टियों से युक्त होगा।

(4) जब किसी सहकारी सोसाइटी ने ऐसा कोई संकल्प पारित कर दिया हो, तो वह अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को उसका लिखित नोटिस देगी और, किसी उप-विधि या संविदा के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी सदस्य या लेनदार को, उस पर नोटिस की तारीख की तारीख से तीन महीने की कालावधि के दौरान, यथास्थिति अपने शेयरों, निक्षेपों या कर्जों को वापस लेने का विकल्प प्राप्त होगा।

(5) कोई सदस्य या लेनदार जो उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प का अनुमोदन कर दिया है।

(6) इस धारा के अधीन सहकारी सोसाइटी द्वारा पारित कोई भी संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि या तो,—

(क) उसके सम्बन्ध में सभी सदस्यों और लेनदारों की अनुमति अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती है, या

(ख) ऐसे सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों का पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया जाता है, जिन्होंने उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट विकल्प का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोग किया है।

(7) जब इस धारा के अधीन सोसाइटी द्वारा पारित संकल्प में किन्हीं आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण अन्तर्बिलित हो, तो संकल्प, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी और हस्तांतरण पत्र के बिना भी अन्तरिस्ती में आस्तियाँ और दायित्व निहित करने के लिए पर्याप्त हस्तांतरण पत्र होगा।

सोसाइटियों के समामेलन, संपरिवर्तन और पुनर्गठन का निर्देश देने की शक्ति।

14-अ. (1) जहाँ रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि लोक हित में या सहकारी आन्दोलन के हित में अथवा किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से यह आवश्यक या वांछनीय है कि दो या उससे अधिक सोसाइटियाँ समामेलित की जानी चाहिए या पुनर्गठित की जानी चाहियें, अथवा सोसाइटी के किसी अन्य वर्ग में संपरिवर्तित की जानी चाहिए या किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों को अपनी आस्तियाँ और दायित्व, पूर्णतः या अंशतः कुल आस्तियों और दायित्वों के समान अनुपात से किसी अन्य सोसाइटी को अन्तरित करने चाहिए, तो अन्तिम पूर्वगामी धारा में किसी बात के होते हुए भी किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसे समामेलन या पुनर्गठन अथवा संपरिवर्तन एसी सोसाइटी या सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण का आदेश, ऐसे गठन, सम्पत्ति, अधिकारों, हितों, दायित्वों, कर्तव्यों और बाधकताओं सहित, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रार, द्वारा संबद्ध सोसाइटी या सोसाइटियों अथवा उसके सदस्यों या लेनदारों और संबद्ध वित्तीय बैंक अथवा बैंकों से भी, मुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के पश्चात् ऐसे मुझावों और आक्षेपों पर जो आमन्त्रित करने की तारीख में साठ दिन के भीतर उस द्वारा प्राप्त किए जाएं, विचार नहीं किया जाता है और ऐसे मुझाव और आक्षेपों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित आदेश में ऐसे परिवर्तन नहीं कर लिए जाते जो उसे वांछनीय प्रतीत हों।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक उपबन्ध हो सकेंगे जो रजिस्ट्रार की राय में यथा स्थिति, समामेलन या पुनर्गठन अथवा संपरिवर्तन या आस्तियां और दायित्वों के अन्तरण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।

(4) ऐसी सोसाइटियों का प्रत्येक सदस्य या लेनदार जो समामेलित या पुनर्गठित या संपरिवर्तित की जानी हैं या जिनकी आस्तियां और दायित्वों को अन्तरित किया जाना हों, जिसने इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे समामेलन या पुनर्गठन या संपरिवर्तित या आस्तियां और दायित्वों के अन्तरण की स्कीम पर आदेशों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आक्षेप किया है और उसका समाधान नहीं हुआ है वह, यथास्थिति, अपने गेयर या हित अथवा निक्षेपों या ऋण अथवा अन्य देय प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने पर धारा 14 की उप-धारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध इस प्रकार समामेलित या पुनर्गठित सोसाइटियों को इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा समामेलन या पुनर्गठन इस धारा के अधीन किया गया था।

15. (1) जब किसी सहकारी सोसाइटी की सभी आस्तियां और दायित्व धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार किसी दूसरी सोसाइटी को अन्तरित कर दिए जाते हैं तो प्रथम वर्णित सोसाइटी को रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और वह सोसाइटी समाप्त समझी जाएगी और नियमित निकाय के रूप में अस्तित्वहीन हो जाएगी।

कुछ दशाओं में सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों का रद्द-करण।

(2) जब धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार दो या अधिक सोसाइटियों को नई सोसाइटी के रूप में समामेलित किया जाता है तब नई सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण पर प्रत्येक समामेलित सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और ऐसी प्रत्येक सोसाइटी समाप्त की गई मानी जाएगी और नियमित निकाय के रूप में अस्तित्वहीन हो जाएगी।

(3) जहां कोई सोसाइटी स्वयं को धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार दो या उससे अधिक सोसाइटियों में विभाजित करती है वहां नई सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण पर उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और वह सोसाइटी समाप्त मानी जाएगी और नियमित निकाय के रूप में अस्तित्वहीन हो जाएगी।

(4) जब सहकारी सोसाइटी धारा 14 के अनुसार एक वर्ग से दूसरे में संपरिवर्तित की जाती है तो उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नई सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण पर रद्द हो जाएगा और सोसाइटी समाप्त मानी जाएगी तथा अस्तित्वहीन हो जाएगी।

16. (1) कोई दो या उससे अधिक सोसाइटियां, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से, प्रत्येक ऐसी सोसाइटी की विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किसी विशिष्ट कारबार या कारबारों के निष्पादन के लिए भागीदारी कर सकेगी, परन्तु यह तब कि प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख के बारे में स्पष्ट दस दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।

सोसाइटियों की भागीदारी।

(2) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की कोई भी बात ऐसी भागीदारी को लागू नहीं होगी।

अध्याय-3

सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों और उसके अधिकार तथा दायित्व

वे व्यक्ति
जो सदस्य
बन सकते
हैं।

17. किसी भी व्यक्ति को, सहकारी सोसाइटी की सदस्यता नहीं दी जाएगी, सिवाय निम्नलिखित के, अर्थात् :—

- (क) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अधीन 1872 का 9 संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति;
- (ख) कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी (समापन कार्यवाहियों के अधीन सोसाइटी के सिवाय) ;
- (ग) राज्य सरकार; और
- (घ) व्यक्तियों या व्यक्तियों के संगम का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा इसे निर्मित अधिसूचित किए जाए।

नामीय या
सहयुक्त
सदस्य।

18. (1) धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी में निम्न प्रकार के सदस्य भी हो सकते हैं :—

- (क) नामीय सदस्य; और
- (ख) सहयुक्त सदस्य।

(2) (क) ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ सहकारी सोसाइटी का कारबार व्यौहार है या जिसके साथ व्यौहार प्रस्तावित है, नामित सदस्य के रूप में सदस्यता दी जा सकती।

(ख) स्कूल भण्डारों या अन्य ऐसी किन्हीं सोसाइटियों में अवयस्क को सहयुक्त सदस्य के रूप में सदस्यता दी जा सकती।

(ग) नामित या सहयुक्त सदस्य को सोसाइटी के लाभ में हिस्से का कोई अधिकार नहीं होगा, ना ही वह समिति की सदस्यता का पात्र होगा, ना ही वह ऐसे विशेषाधिकारों और अधिकारों के लिए सदस्य पर अधिमानता का हकदार होगा जो सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी नामित या सहयुक्त सदस्य को सदस्य के ऐसे विशेषाधिकार और अधिकार होंगे जो सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

सदस्यों द्वारा
तब तक
अधिकारों
का प्रयोग
न किया
जाना जब
तक देय
का संदाय
नहीं कर
दिया जाता।

19. सोसाइटी का कोई भी सदस्य, तब तक सदस्य के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा जब तक वह सदस्यता के बारे में सोसाइटी को ऐसा संदाय नहीं कर देता है या वह सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित नहीं कर लेता है, जो ऐसी सोसाइटी के नियमों या उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

20. सोसाइटी के कार्यकलाप में सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ; परन्तु :—

सदस्यों के मत ।

- (क) नामित या सहयुक्त सदस्य को मत का अधिकार नहीं होगा ;
- (ख) मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ;
- (ग) जहां सरकार सोसाइटी की सदस्य है वहां धारा 35 के अधीन समिति में नाम निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या धारा 35-आ के अधीन नियुक्त प्रबन्ध निदेशक का एक मत होगा ;
- (घ) जहां सोसाइटी का शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है, वहां केवल एक व्यक्ति को, जिसका नाम शेयर प्रमाण-पत्र में और इसकी अनुपस्थिति में सदस्य, रजिस्टर में प्रथम स्थान पर हो, एक मत देने का अधिकार होगा ; और
- (च) उपविधियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अव्यक्त जिसे धारा 23 के अधीन किसी मृत सदस्य का शेयर अन्तरित किया गया है, मत देने का हकदार नहीं होगा ।

21. (1) सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपना मत स्वयं देगा और कोई भी सदस्य परोक्षी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।

मत देने की रीति ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, वह सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी की सदस्य है, अपने सदस्यों को इतनी संख्या में जैसी विहित की जाए, ऐसी अन्य सोसाइटी के कार्यकलापों में मत देने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

22. (1) सोसाइटी की पूंजी के शेयर या हित का अन्तरण ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगा जैसी कि अधिकतम षट्ति के बारे में धारा 6 में विनिर्दिष्ट की गई है ।

(2) कोई सदस्य उस द्वारा धारित किसी शेयर या किसी सोसाइटी की पूंजी अथवा सम्पत्ति में अपने हित या प्रत्येक उसके किसी भाग को तब तक अन्तरित नहीं करेगा जब तक कि—

शेयर या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन ।

- (क) उसने ऐसे शेयर या हित को कम से कम एक वर्ष के लिए धारित नहीं किया हो ;
- (ख) अन्तरण, सोसाइटी या सोसाइटी के सदस्य अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसका सदस्यता के लिए आवेदन सोसाइटी द्वारा स्वीकृत किया गया है, नहीं किया जाता है ;
- (ग) समिति ने ऐसे अन्तरण को अनुमोदित न किया हो

23. (1) सोसाइटी के सदस्य की मृत्यु पर सोसाइटी मृत सदस्य का शेयर या हित नियमों के अनुसार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को या यदि कोई व्यक्ति नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति के जो समिति को मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, अन्तरित करेगी :

सदस्य की मृत्यु पर हित का अन्तरण ।

परन्तु यह तब, जब कि, यथास्थिति, ऐसे नाम-निर्देशिनी, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को, सोसाइटी का सदस्य बनाया जाए :

परन्तु यह और कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी अवस्तक या किसी विकृत-चत व्यक्ति को विरासत द्वारा या अन्यथा, सहकारी सोसाइटी में मृत सदस्य के शेयर या हित को अर्जित करने से निर्धारित नहीं करेगी ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, ऐसी कोई नाम-निर्देशिनी, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, सोसाइटी से उसे नियमों के अनुसार मृत सदस्य के शेयर या हित के अभिविधिचित मूल्य का संदाय किए जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(3) सोसाइटी, मृत सदस्य को सोसाइटी से देय सभी अन्य राशियों का, यथास्थिति, ऐसे नाम निर्देशित, बरिस या विधिक प्रतिनिधि को सँदाय कर सकेगी।

(4) इस धारा के अनुबन्धों के अनुसार सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अन्तरण और सँदाय, सोसाइटी से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई किसी मांग के विरुद्ध विधिमान्य और प्रभावी होंगे।

निष्कासित
या पद त्याग
किए हुए
या उन्मत्त
सदस्य के
शेयर या
हित का
व्यय न।

24. जब सोसाइटी का कोई सदस्य नियमों या उप-नियमों के अनुसार निष्कासित किया जाता है या पदत्याग करता है, अथवा कोई सदस्य उन्मत्त हो जाता है तो,—

(क) उसका शेयर या हित अन्य व्यक्ति को जो धारा 22 के उपबन्धों के अनुसार अन्तरित होने के लिए अर्हित हो, अन्तरित किया जाएगा, और नियमों के अनुसार अवधारित उसका मूल्य ऐसे सदस्य को या, यदि वह उन्मत्त है, तो भारतीय पागलपन अधिनियम, 1972 के अधीन उसकी सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को, सँदत्त किया जाएगा; या

1972 का 4

(ख) अपरिसीमित दायित्व वाली किसी सोसाइटी की दशा में, यदि उपविधियों में ऐसा उपबन्ध हो, तो नियमों के अनुसार अवधारित उसके शेयर या हित का मूल्य उसे या यदि वह उन्मत्त है, तो भारतीय पागलपन अधिनियम, 1972 के अधीन उसकी सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को, सँदत्त किया जाएगा।

1972 का 4

निष्कासित
या पदत्याग
किए हुए
अथवा
उन्मत्त सद-
स्यों को
देय धनराशि
का व्ययन।

25. सोसाइटी के ऐसे सदस्य को शेयर या हित के बारे में सँदायों के भिन्न, नियमों के अनुसार संगठित सभी राशियाँ जो सदस्य को किसी सोसाइटी द्वारा देय होंगी, धारा 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित को सँदत्त की जाएंगी :—

(क) उस सदस्य की दशा में जो सोसाइटी से निष्कासित किया गया है या जिसने पद त्याग कर दिया है, उसे; और

(ख) उस सदस्य की दशा में जो उन्मत्त हो गया है, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1972 के अधीन उसकी सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को।

1972 का 4

सदस्यों का
पुस्तकें
आदि देखने
का अधि-
कार।

26 (1) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर सभी युक्तियुक्त समयों पर, अपने सदस्यों या गैर-सदस्यों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए निम्नलिखित को खुला रखेगी :—

(क) इस अधिनियम की एक प्रति ;

(ख) नियमों की एक प्रति ;

(ग) सोसाइटी की उपविधियों की एक प्रति; और

(घ) सदस्यों का रजिस्टर।

(2) सोसाइटी के सभी रजिस्टर और अभिलेख, सिवाय अपने लेखों से भिन्न लेखों से सम्बद्ध पुस्तकें और अन्य दस्तावेजों के ऐसी सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा, ऐसी फीस के सँदाय पर, जो उप-विधियों में विहित की जाए, के सोसाइटी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(3) ऐसी शर्तों और ऐसी फीसों सँदाय के अधीन रहते हुए जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके किसी सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर सोसाइटी, उसे ऐसे अभिलेखों या रजिस्ट्रों अथवा उनके उद्धरणों की प्रमाणित प्रति देगी।

27 धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की पूंजी में सदस्य का शेयर या हित अथवा अभिदाय ऐसे सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के बारे में, किसी न्यायालय की किसी डिक्ली या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्व के अधीन नहीं होगा, न ही प्रातीय दीबाला अधिनियम, 1920 के अधीन कोई रिमीवर, ऐसे शेयर या हित अथवा अभिदाय पर किसी दावे का हकदार होगा।

शेयर या हित का कुर्की के दायित्व अधीन न होता।

28. सोसाइटी के सदस्य, सोसाइटी के सम्पादन पर सोसाइटी की आस्तियों में किसी कमी के प्रति अभिदाय करने के संयुक्ततः और पृथकतः संयुक्त तथा निम्नलिखित दायित्व के अधीन होंगे :—

सदस्यों का दायित्व।

- (क) अपरिसीमित दायित्व वाली किसी की दशा में, बिना सीमा के; और
- (ख) परिसीमित दायित्व वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, राशि की ऐसी परिसीमा के अधीन रहते होंगे, जिसका उप-विधियों में उपबन्ध किया जाए।

29. (1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहकारी सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को सम्पदा का सोसाइटी के निम्नलिखित को विद्यमान ऋणों के लिए दायित्व :—

भूतपूर्व सदस्य और मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व।

- (क) किसी भूतपूर्व सदस्य की दशा में, उस तारीख को जिसको वह सदस्य नहीं रहा;
- (ख) किसी मृत सदस्य की दशा में उसकी मृत्यु की तारीख को, ऐसी तारीख से दो वर्षों की कालावधि के लिए बना रहेगा।

(2) जहां धारा 78 के अधीन सहकारी सोसाइटी का परिस्मापन करने के लिए आदेश किया जाता है वहां किसी ऐसे भूतपूर्व सदस्य का या किसी मृत सदस्य को सम्पदा का दायित्व, जो परिस्मापन करने के आदेश के प्रभावी होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के भीतर सदस्य नहीं रहा या मर गया, तब तक बना रहेगा, जब तक सम्पूर्ण समापन कार्यवाहियां पूरी नहीं हो जाती, किन्तु ऐसे दायित्व का विस्तार सोसाइटी के ऐसे ऋणी तक ही होगा, जो यथास्थिति, उनके सदस्य न रहने की या उनकी मृत्यु की तारीख को विद्यमान थे।

30. (1) निम्नलिखित द्वारा अपनी आस्तियों और दायित्वों का पूर्ण, सही और ठीक विवरण दिया जाएगा,—

सदस्यों द्वारा अपनी वित्तीय सह-मति और स्थावर सम्पत्ति के अन्य संक्रामण की सूचना।

- (क) अपरिसीमित दायित्व वाली किसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ;
- (ख) अपरिसीमित दायित्व वाली किसी सोसाइटी के सदस्य द्वारा जब रजिस्ट्रार या उस द्वारा सान्मान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या वित्तीय बैंक द्वारा, ऐसा करने की अपेक्षा की जाए; और
- (ग) किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य द्वारा ऋणी के लिए या प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत किए जाने के लिए किसी आवेदन के साथ।

(2) सोसाइटी का सदस्य प्रत्येक संव्यवहार के पूरा होने से पूर्व, उस सोसाइटी को जिसका वह सदस्य है, अपनी स्थावर सम्पत्ति या उसके किसी भाग या शेयर के किसी विक्रय, बन्धक, या किसी रूप में, चाहे जो भी हो, अन्तरण के सम्बन्ध में और ऐसी सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उपगत किए जान वाले किसी प्रस्तावित ऋण के सम्बन्ध में पूर्ण सही और ठीक सूचना देगा।

अध्याय-4

सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध

सहकारी
सोसाइटी
में अन्तिम
प्राधिकार।

31. सहकारी सोसाइटी में अन्तिम प्राधिकार, साधारण बैठक में सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा :

परन्तु यह कि जहां सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों में ऐसी उप-विधियों के अनुसार निर्वाचित या चयनित सोसाइटी के सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित लघुतर निकाय के गठन का उपबन्ध किया है, वहां लघुतर निकाय साधारण निकाय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं या सोसाइटी की उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाएं :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात, सहकारी सोसाइटी की समिति या किसी अधिकारी को नियमों या उप-विधियों द्वारा प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

वार्षिक
साधारण
बैठक।

32. (1) प्रत्येक सोसाइटी की एक साधारण बैठक प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की जाएगी:—

- (क) आगामी वर्ष के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए सोसाइटी के कार्यक्रमलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन ;
- (ख) नामनिर्दिष्ट सदस्यों से अन्यथा सगति के सदस्यों का, विहित रीति में निर्वाचन, यदि कोई हो ;
- (ग) लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार ;
- (घ) शुद्ध लाभ का व्ययन ; और
- (ङ) किसी अन्य विषय पर विचार जो उप-विधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

(2) ऐसी साधारण बैठक उप-धारा (1) के अधीन की गई अन्तिम पूर्वगामी बैठक की तारीख से पन्द्रह महीनों से अधिक के पश्चात् नहीं की जाएगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी बैठक करने की अवधि में तीन मास से अधिक अवधि की और वृद्धि कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि, रजिस्ट्रार की राय में ऐसी वृद्धि आवश्यक नहीं है या उस द्वारा वृद्धि की गई अवधि (यदि कोई है) के भीतर सोसाइटी द्वारा ऐसी बैठक बुलाई जाती है, तो रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति विहित रीति से ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से बुलाई गई साधारण बैठक मानी जाएगी, और रजिस्ट्रार यह आदेश कर सकेगा कि ऐसी बैठक बुलाने में उपगत व्यय, सोसाइटी की विधियों में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो, रजिस्ट्रार की राय में, साधारण बैठक बुलाने की इन्कारी या अतफलता के उत्तरदायी हैं, संदत्त किया जाएगा।

33. (1) विशेष साधारण बैठक: प्रधान द्वारा या समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकेगी और निम्नलिखित पर यह एक माम के भीतर बुलाई जाएगी:—

विशेष
साधारण
बैठक।

- (क) सोसाइटी के सदस्यों के पांचवें भाग या सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा जो इस प्रयोजन के लिए उप-विधियों में विनिर्दिष्ट है, जो भी निम्न हो, की लिखित अध्यापेक्षा पर; या
- (ख) रजिस्ट्रार की प्रेरणा पर, या
- (ग) ऐसी सोसाइटी की दशा में जो संघ सोसाइटी की सदस्य है, ऐसी संघ सोसाइटी की समिति के अनुरोध पर।

(2) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यापेक्षा के अनुसार किसी सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो रजिस्ट्रार या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, ऐसी बैठक बुलाएगा, और वह बैठक समिति द्वारा अस्यक् रूप से बुलाई गई बैठक मानी जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार को वह आदेश करने की शक्ति होगी कि उप-धारा (2) के अधीन बैठक बुलाने में उपगत किया गया व्यय, सोसाइटी की निधियों में से या ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जो रजिस्ट्रार की राय में बैठक बुलाने की इन्कार या असफलता के लिए उत्तरदायी हैं, संदत्त किया जाएगा।

34. प्रत्येक सोसाइटी का प्रबन्ध नियमों और उपविधियों के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जैसे कि कानून: इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किया जाए।

प्रबन्ध
समिति।

35. (1) (क) जहां राज्य सरकार ने,—

- (i) सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में अभिदाय किया है; या
- (ii) सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी के निर्माण या वृद्धि में परोक्षतः सहायता की है जैसा कि धारा 48 के अधीन उपबन्धित है; या
- (iii) सोसाइटी को किसी मूलधन के पुनः संदाय और ऋणों और अग्रिमों पर व्याज के संदाय की गारंटी दी है;

सहकारी
सोसाइटी
की समिति।

वहां राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को, सोसाइटी की समिति के, ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तीन सदस्यों से अनधिक या सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई को, जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि जहां सरकार ने सहकारी सोसाइटी को शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये तक या उससे अधिक अभिदाय किया है वहां सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी सरकार, पूर्वोक्त रीति में नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, एक अन्य सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और उसे प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(ख) जहां नियोजक ने अपने कर्मचारियों की सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी

में पांच हजार रुपये तक या उससे अधिक अभिदाय किया है, वहां नियोजक को ऐसी सोसाइटी की समिति में दो सदस्य या कुल सदस्यों का एक तिहाई, जो भी कम हो, नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

(ग) जहां सरकार द्वारा इस निमित्त प्रधिसूचित किसी वित्तीय संस्था ने सहकारी सोसाइटी का वित्त पोषण किया है वहां ऐसी वित्तीय संस्था को समिति में एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सहकारी सोसाइटी की समिति में नामनिर्दिष्ट सदस्य, यथास्थिति, राज्य सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा नियोजक या वित्तीय संस्था के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) जहां ऐसी सहकारी सोसाइटी में, जिसमें सरकार द्वारा सोसाइटी की काम-काज पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक शेयर का अभिदाय किया है या उधार लने के लिए गारंटी द्वारा दायित्व अपने ऊपर लिया है वहां किसी मामले के बारे में उप-धारा (1) (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट समिति के किसी सदस्य और उसके अन्य सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में वह मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे प्रवर्तित होगा माना कि यह समिति का विनिश्चय हो।

कुछ दशाओं में नई विधियों के अनुसार गठित समिति विद्यमान नहीं है, वहां रजिस्ट्रार, इस अधिनियम या नियमों अथवा उप-विधियों में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा गठित करने ऐसी सोसाइटी के लिए ग्यारह से अनधिक सदस्यों से गठित समिति का गठन कर सकेंगे जिसमें से कम से कम एक तिहाई ऐसी सोसाइटी के शेयर धारक होंगे, जैसे वह उचित समझे :

परन्तु यदि इस प्रकार गठित समिति के सदस्यों की संख्या ग्यारह से कम हो तो रजिस्ट्रार, समय-समय पर, समिति में एक सदस्य या सदस्यों का परिवर्तन कर सकेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति, इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के सभी प्रयोजनों के लिए समिति मानी जाएगी और यह दो वर्ष की कालावधि के लिए या उस कालावधि तक जब तक कि ऐसी सोसाइटी के लिए अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार समिति का गठन नहीं कर दिया जाता, जैसा भी पहले समाप्त हो, कार्य करती रहेगी :

परन्तु सरकार अधिसूचना द्वारा दो वर्ष की कालावधि में ऐसी वृद्धि कर सकेंगी ताकि कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक न हो।

प्रवन्ध 35-अ. (1) जहां सरकार ने सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में पांच लाख निदेशकों रुपये तक या उससे अधिक का अभिदाय किया है वहां सरकार, उपविधियों में किसी की नियुक्ति, बात के होते हुए भी, धारा 35 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, कोई शक्तियां द्वारा सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेंगी और उस प्रबंध निदेशक नियुक्त कर और हटायें सकेंगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी के प्रबंध निदेशक के रूप में

नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा का सदस्य नहीं है या सहकारी विकास का वर्ग-I अधिकारी नहीं है, बिना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी भू-विकास बैंक और हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध परिसंघ (केन्द्र) के जहाँ तकनीकी व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नाननिर्दिष्ट और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति समिति का पदेन सदस्य होगा और राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और उसे समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने और मतदान करने का भी अधिकार होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उप-विधियों के अधीन उसे सौंपी जाएं या समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं। वह उप-विधियों से संगत सभी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कि जो उसे सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा सौंपे जाएं। वह समिति के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(4) सहकारी सोसाइटी का प्रबंध निदेशक इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। सहकारी सोसाइटी के सभी कर्मचारी उसके अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेंगे और कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(5) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रबंध निदेशक सहकारी सोसाइटी में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उसका वेतन और भत्ते सोसाइटी की निधियों में से संदत्त किए जाएंगे।

36. राज्य सरकार सोसाइटी के आवेदन-पत्र पर और ऐसी शर्तों पर जो विहित की जाएं, सरकारी सेवक को सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए उसकी सेवा में प्रतिनियुक्ति कर सकती और इन प्रकार प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं।

सहकारी सोसाइटी के कार्य-कलापों का प्रबंध करने के लिए सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्त करने की शक्तियां।

37. यदि रजिस्ट्रार की राज्य में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या उसका कोई सदस्य बार-बार इस अधिनियम या नियमों अथवा उप-विधियों द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में वृत्तिक्रम या उपेक्षा करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है, जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो तो रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी समिति या सदस्य को अपने आक्षेपों का, यदि कोई हो, विवरण देने का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा,—

समिति का अधिक्रमण।

(क) समिति को हटा सकेगा ; और

(i) समिति के नए निर्वाचन का आदेश दे सकेगा ; या

(ii) सोसाइटी के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए एक या अधिक प्रशासकों को, जिनके लिए सोसाइटी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, आदेश में विनिर्दिष्ट एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा, और वह अवधि रजिस्ट्रार के विवेकानुसार समस्त-समय पर ऐसे बढ़ाई जा सकेगी ताकि संकलित अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो ; या

(ख) सदस्य को हटा सकेगा और पदावरोही सदस्य की शेष अवधि के लिए

रिक्ति को इस अधिनियम, नियमों तथा उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार भरवा सकेगा।

(1-अ) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कार्यवाहियों की अवधि के दौरान समिति या किसी सदस्य का निलम्बन सहकारी सोसाइटी के हित में आवश्यक है वहाँ वह, यथास्थिति, ऐसी समिति या सदस्य को निलम्बित कर सकेगा, और जहाँ समिति निलम्बित की जाती है वहाँ वह कार्यवाहियों के पूरा होने तक सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जसी वह उचित समझे।

परन्तु यदि इस प्रकार निलम्बित समिति या सदस्य हटाया नहीं जाता है, तो इसे या उसे बहाना किया जाएगा और निलम्बन अवधि की इसकी या उसकी पदावधि में गणना होगी।

(2) रजिस्ट्रार, प्रशासक के लिए ऐसा पारिश्रमिक नियत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे, ऐसा पारिश्रमिक सोसाइटी की निधियों से संदत्त किया जाएगा।

(3) प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियन्त्रण और उसके अनुदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अधीन रहते हुए समिति या सोसाइटी के किसी अधिकारी के कृत्यों में से सभी या किसी का निर्वहन करने और ऐसी सभी कार्यवाहियाँ करने की शक्ति होगी जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।

(4) प्रशासक, अपनी पदावधि की समाप्ति पर, सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार नई समिति के गठन के लिए व्यवस्था करेगा।

(5) सहकारी सोसाइटी के बारे में उप-धारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व रजिस्ट्रार, उन वित्तीय संस्थाओं से जिनकी वह ऋणी है, परामर्श करेगा।

(6) वह सदस्य जो उप-धारा (1) के अधीन हटाया जाता है, किसी समिति में निर्वाचित किए जाने के लिए तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए जो रजिस्ट्रार नियत करे, निरहित किया जा सकेगा और उक्त अवधि उस समिति की जिससे उसे हटाया जाता है पदावधि की समाप्ति के पश्चात् प्रारम्भ होगी।

अभिलेखों
का कब्जा
लेना।

38. (1). (क) जब रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि सोसाइटी की लेख-बहियों और अभिलेखों को विलोपित किया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना सम्भाव्य है या सोसाइटी की निधियों और सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया जाना सम्भाव्य है; या

(ख) यदि सहकारी सोसाइटी की समिति का सोसाइटी की किसी साधारण बैठक में पुनर्गठन किया जाता है या सोसाइटी की समिति धारा 37 के अधीन हटाई जाती है या यदि सोसाइटी को धारा 78 के अधीन परिसमापन आदेश किया जाता है और समिति के पदावधिही सदस्य सोसाइटी के अभिलेखों और सम्पत्ति का भारसाधन, यथास्थिति नई समिति या प्रशासक अथवा समापक को सौंपने से इन्कार करते हैं,

तो रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, उस मैजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारिता

के अन्दर सोसाइटी कार्य कर रही है, अभिलेखों और सम्पत्ति का अभिग्रहण करने और कब्जा करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर मैजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षण की पकट से पीछे का न हो, किसी स्थान में जहाँ अभिलेख और सम्पत्ति रखी जाती है या उनके रखे जाने के बारे में विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने और तलाशी करने के लिए और उन्हें अभिगृहीत करने के लिए और, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या नई समिति अथवा सोसाइटी के प्रशासक या समापक को सौंपने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

अध्याय-5

सहकारी सोसाइटियों के कर्तव्य और बाध्यताएं

39. प्रत्येक सहकारी सोसाइटी नियमों के अनुसार पता रजिस्ट्रीकृत करवाएगी जिस पर सभी नोटिस और संसूचनाएं भेजी जा सकें और वह पते में किसी परिवर्तन का लिखित नोटिस, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के अन्दर रजिस्ट्रार को भेजेगी।

सोसाइटीयों का पता।

40. (1) प्रत्येक सदस्य, सोसाइटी के सदस्यों को इसकी उपविधियों के उपबंधों के अधीन उपलब्ध सेवाओं का हस्ताक्षर होगा और ऐसी सेवाएं उपलब्धता के अधीन रहते हुए, समिति को इसके आवेदन करने पर, दी जाएंगी।

सदस्यों का सोसाइटी द्वारा सेवा के प्रति अधिकार और प्रति-तोष के लिए आवेदन।

(2) यदि किसी सदस्य को किसी सेवा से इन्कार किया जाता है या जहाँ सेवाओं के लिए उसके आवेदन पर, समिति का विनिश्चय उसे ऐसे आवेदन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अन्दर संसूचित नहीं किया जाता है, वहाँ वह रजिस्ट्रार को, यथास्थिति, इन्कार के विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अन्दर या सोसाइटी को आवेदन की तारीख से साठ दिन के अन्दर प्रतितोष के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि सेवा से इन्कारी अनुपयुक्त या युक्तियुक्त, अनुचित या अदेभावपूर्ण है तो वह, समिति को अपना प्रतिवेदन करने के लिए अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा समिति को सेवा करने के लिए निर्देश कर सकेगा।

41. सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक सदस्य सोसाइटी के संव्यवहार या कारबार के बारे में ऐसी सूचना देगा जैसी कि रजिस्ट्रार या लेखा परीक्षक, मध्यस्थ, समापक अथवा निरीक्षक या जांच कर रहे व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित हों।

सूचना देने का दायित्व।

अध्याय-6

सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार

42. सोसाइटी का, पूंजी के अंश में या हित में, और सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के निक्षेपों पर और सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को स्थायी

सदस्यों के शेयर या

हित के बारे में मांग या ऋण पर जिसकी सहकारी सोसाइटी देनदार है, देय किसी लाभांश, बोनस या लाभ पर प्रभार होगा और सोसाइटी ऐसे किसी ऋण के संदाय में या उसके और मुजरा प्रति ऐसे सदस्य के खाते में जमा या देय धनराशि को मुजरा कर सकती :

परन्तु किसी भी सहकारी बैंक का इसके पास सोसाइटी द्वारा धारा 56 के अधीन उसके द्वारा स्थापित भविष्य निधि या उसकी आरक्षित निधि में से निक्षेपित किसी धनराशि पर प्रभार नहीं होगा ; और कोई भी सहकारी बैंक सोसाइटी द्वारा देय किन्हीं ऋणों के प्रति किसी ऐसी धनराशि को मुजरा करने का हक्कदार नहीं होगा ।

सदस्यों का रजिस्टर । 43. किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा रखा गया सदस्यों या अंशों का कोई रजिस्टर । रजिस्टर अथवा सूची उसमें दर्ज किन्हीं निम्नलिखित विधिष्टियों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा :—

(क) वह तारीख जिसको ऐसे रजिस्टर या सूची में किसी व्यक्ति का सदस्य के रूप में नाम दर्ज किया गया था ;

(ख) वह तारीख जिसको ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहा ।

सोसाइटी की बहियों में प्रविष्टियों का सबूत । 44. (1) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के कारबार के दौरान नियमित रूप से रखी गई वही को किसी प्रविष्टि की प्रति यदि ऐसी रीति में प्रमाणित की जाती है जो विहित की जाए, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाही में ऐसी प्रविष्टि की विद्यमानता के रूप में ग्रहण की जाएगी और प्रत्येक मामले में, उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखों में, उसी सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण होगी, जिन तक मूल प्रविष्टि ग्राह्य है ।

(2) सोसाइटी के किसी अधिकारी को और किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसका कार्यालय में किसी सोसाइटी की बहियां समाप्त के पश्चात जमा करवाई जाती हैं, किन्हीं भी विधिक कार्यवाहियों में जिसमें सोसाइटी या समाप्त पक्षकार नहीं है, न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा विषय हस्तक के लिए किए गए आदेश के सिवाय सोसाइटी की बहियों या दस्तावेजों को जिसकी विषय वस्तु इस धारा के अधीन आवृत्ति की जा सकती है, पेश करने के लिए या उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में पेश होने के लिए, विवश नहीं किया जाएगा ।

लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट ।

45. भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

1908 का
10

- (1) सोसाइटी की आस्तियों के पूणतः या भागतः स्थावर सम्पत्ति के रूप में होते हुए भी, सोसाइटी में अंश से सम्बन्धित कोई लिखत ; या
- (2) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए स्थावर सम्पत्ति में किसी अधिकार, हक या हित को सृजित, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या समाप्त करने वाला कोई डिबेंचर, सिवाए वहां तक जहां तक वह उसका धारक को किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा (प्रदान की गई प्रतिभूति) का हकदार बनाता है जिसका द्वारा सोसाइटी ने ऐसे डिबेंचर धारियों के लाभ के लिए

अपनी सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका भाग अथवा उसमें कोई हिस्सा न्यायियों को न्याय के रूप में बन्धक रखा है या हस्तांतरित अथवा अन्यथा अन्तरित किया है।

(3) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए किसी डिवेंचर पर पृष्ठांकन या उसका अन्तरण।

46. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी सोसाइटी के पक्ष में यह उद्बन्धित करने वाला कोई करार निष्पादित कर सकता कि उसका नियोजक उसे नियोजक द्वारा संदेय वेतन या मजदूरी में से ऐसी राशि को जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए कटौती करने और इस प्रकार काटी गई राशि को सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण या अन्य मांग की श्रृष्टि में सदत्त करने के लिए सक्षम होगा।

कतिपय
दशाओं में
सोसाइटी
के दावों को
पूरा करने
के लिए वेतन
में कटौती।

(2) ऐसे करार के निष्पादन पर, नियोजक, यदि सोसाइटी द्वारा लिखित रूप में प्रत्यपेक्षा द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए और जब तक सोसाइटी यह सुचित न करे कि ऐसे संपूर्ण ऋण या मांग का संदाय कर दिया गया है, करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई राशि कटौती की तारीख में चौदह दिन के अन्दर सोसाइटी संदाय करेगा।

(3) यदि पूर्वगामी उपधारा के अधीन की गई अध्यापेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् नियोजक संबद्ध सदस्य को संदेय वेतन या मजदूरी से अध्यापेक्षा में विनिर्दिष्ट राशि की कटौती करने में आफन रहता है या काटी गई राशि सोसाइटी को भेजने में व्यतिक्रम करता है, तो नियोजक उसके संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा और सोसाइटी की ओर से राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसुलीय होगी, और इस प्रकार देय राशि को नियोजक के ऐसे दायित्व के बारे में वैसे ही दर्जा में प्राथमिकता प्राप्त होगी जैसी बकाया मजदूरी की प्राप्ति होती है।

47. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) कोई व्यक्ति जो सोसाइटी को जिसका वह सदस्य है उधार के लिए आवेदन करता है, यदि वह किसी भूमि का स्वामी है या किसी अभिधारी के रूप में किसी भूमि में उसका हित है, वह विहित प्ररूप में घोषणा करेगा। ऐसी घोषणा में यह कथन किया जाएगा कि आवेदक एतद्वारा उसके द्वारा घोषणा में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि या हित पर आवेदन के अनुसरण में सोसाइटी द्वारा सदस्य को दिए जाने वाले उधार की राशि के और उसके द्वारा अपेक्षित सभी भावी अग्रिमों के, यदि कोई हो, जो सोसाइटी ऐसी अग्रिमतम सीमा के अधीन रहते हुए जो वह अवधारित करे, ऐसे सदस्य के रूप में उसे दे, ऐसे उधार की राशि और अग्रिम पर व्यय सहित, संदाय के लिए भार का सृजा करता है ;

(ii) कोई व्यक्ति जिसने सोसाइटी से जिसका वह सदस्य है इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व कोई ऋण लिया है और जो किसी भूमि का स्वामी है या अभिधारी के रूप में किसी भूमि में कोई हित रखता है और जिसने पूर्वोक्त तारीख से पहले ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रखी है, तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, खण्ड (i) में निर्दिष्ट आशय की घोषणा उसमें

कतिपय
सोसाइटियों
से उधार
लेने वाले
सदस्यों को
स्थावर
सम्पत्ति पर
भार।

निर्दिष्ट पक्षा में करेगा, और कोई व्यक्ति जब तक उसने ऐसी घोषणा नहीं की हो तब तक सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी अधिकार को प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ;

(iii) खण्ड (i) या (ii) के अधीन की गई घोषणा सदस्य द्वारा, सोसाइटी की सम्पत्ति से जिसके पक्ष में ऐसा भार सृजित किया गया है, किसी भी समय परिवर्तित की जा सकती ;

(iv) कोई भी सदस्य खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण भूमि या उसका कोई भाग अथवा हित तब तक अन्य संक्रांत नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा उधार ली गई सम्पूर्ण राशि उस पर ब्याज सहित पूर्णतः सदातः नहीं कर दी जाती है :

परन्तु ऐसी किसी भूमि पर खड़ी फसल सोसाइटी को पूर्व अनुज्ञा से अन्य संक्रान्त की जा सकती :

परन्तु यह और कि यदि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गई राशि के किसी भाग का संदाय कर दिया जाता है, तो सोसाइटी सदस्य के आवेदन पर, खण्ड (i) या (ii) के अधीन की गई घोषणा के अन्तर्गत सृजित भार से, उक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट जंगम या स्थावर सम्पत्ति के ऐसे भाग को निमुक्त कर सकती जैसा कि वह सदस्य से, बकाया रहने वाली राशि के शेष की प्रतिभूति को ध्यान में रखते हुए, समुचित समझे :

परन्तु यह और कि भूमि पर कोई भार सृजित नहीं किया जाएगा यदि दिए गए ऋण की राशि ऐसी राशि से कम है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और किसी सदस्य को ऐसा ऋण उसके अपने साथी सदस्यों में से दो प्रतिभूतियां देने पर अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(v) खंड (iv) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई अन्य संक्रामण ग्राह्य होगा ;

(vi) भूमि राजस्व के सम्बन्ध में सरकार के पूर्व दावों के अधीन रहते हुए खण्ड (i) या (ii) के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट भूमि या हित पर उसके द्वारा ऋणों और अग्रिम के कारण देय राशियों के लिए और उनके परिमाण तक सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगा ;

(vii) अधिकार अभिलेख में खण्ड (i) या (ii) के अधीन घोषणा के अन्तर्गत सृजित भूमि अथवा हित पर प्रत्येक भार की विशिष्टियां होंगी । हल्का पटवारी घोषणा की प्राप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर ऐसे भार को ग्राम अभिलेख में लिखेगा और तत्पश्चात् घोषणा को सम्बद्ध सोसाइटी को लौटा देगा ।

सहकारी
सोसाइटियों
को राज्य-
सहायता के
अन्य रूप ।

48. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार,—

(क) सहकारी सोसाइटी की अंशपूजी में अभिदाय कर सकती ;

(ख) सहकारी सोसाइटी को ऋण या अभिदाय दे सकती ;

(ग) सहकारी सोसाइटी की अंश पूजी के प्रति संदाय और उस पर ऐसी दरों से लाभांश की, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, गारंटी दे सकती ;

(घ) सहकारी सोसाइटी को दिए गए ऋणों और अग्रिम के मूलधन का प्रतिसंदाय और उन पर ब्याज का संदाय, गारंटी दे सकती ; और

(ङ) किसी सोसाइटी को किसी अन्य रूप में वित्तीय सहायता जिसके अन्तर्गत सहायकी भी है, दे सकती ।

(1963 का 36) 49. (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 के किन्हीं अन्य उपबन्धों के होते हुए परिसीमा भी, सांसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा देय किसी राशि की जिसके अन्तर्गत उसका व्यय भी है, बसूली के लिए बाद के संस्थित करने के लिए परिसीमा अवधि की गणना ऐसे सदस्य की मृत्यु की या उसके सांसाइटी के सदस्य न रहने की तारीख से की जाएगी।

1963 का 36 (2) परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध इस अधिनियम की धारा 73 के अधीन की गई कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे।

50. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा सहकारी सोसाइटीयों के किसी श्रेणी के लाभों या ऐसी सोसाइटीयों के किसी श्रेणी के सदस्यों द्वारा लाभ के रूप में प्राप्त लाभों या अन्य संदायों के सम्बन्ध में देय आधिकार से छूट दे सकेगी।

कुछ करों, फीसों और शुल्कों से छूट।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी सोसाइटी या सांसाइटी के वर्ग के बारे में निम्न-लिखित को छूट दे सकेगी :—

(क) सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से अथवा उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा निष्पादित और ऐसी सोसाइटी के कारबार से सम्बन्धित किसी लिखित या ऐसी लिखतों के किसी वर्ग के बारे में या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय या आदेश के बारे में उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रभाय स्टाम्प शुल्क, ऐसी दशाओं में जहाँ ऐसी छूट के अभाव में यथास्थिति, सहकारी सोसाइटी, अधिकारी या सदस्य ऐसा स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी होगा ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में संदेय फीस या न्यायालय फीस।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट पत्तों, चैकों, वचन-पत्रों, वाहन-पत्रों, क्रेडिट पत्रों बीमा पालिसियों, अंशों का अन्तरण, डिबेंचरों, परोक्षी और रसीदों के बारे में स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में "सरकार" से केन्द्रीय सरकार और पूर्वोक्त के सिवाय राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटीयों के वर्ग को निम्न-लिखित से छूट दे सकेगी :—

(क) भू-राजस्व;

(ख) कृषि आय पर कर;

(ग) माल के विक्रय या क्रय पर कर; और

(घ) व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर।

1920 का 5

51. प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि में किसी बात के होते हुए भी, सदस्य स सोसाइटी की देय रकमों उसके विरुद्ध दिवाला कार्यवाहियों में, प्राथमिकता के क्रम में उस द्वारा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय रकमों के ठीक नीचे आएंगी।

सदस्यों का दिवाला।

52. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व या भू-राजस्व के रूप में बसूली किसी धन के बारे में सरकार के किसी पूर्वाधिकार दावे के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य का या मृत सदस्य द्वारा सहकारी सोसाइटी

कतिपय जास्तियों पर सहकारी

सोसाइटियों को देय कोई ऋण या बचत भाग, जवाबदारी, ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य की प्रत्येक का प्रथम मृत सदस्य की समादा की भाग रूप (जंगम सम्पत्ति), फसल और अन्य कृषि उपज, पशुओं, के लिए चारे, कृषि सम्बन्धी या औद्योगिक सम्बन्धी उपकरणों या मशीनरी विनिर्माण के लिए कच्चे माल और ऐसे कच्चे माल से तैयार किसी उत्पाद पर प्रथम भार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी समाप्ति का जो उप-धारा (1) के अधीन भारग्रस्त है भारधारी, सहकारी सोसाइटी की निम्नित पूर्व अनुज्ञा के सिवाय अन्तरण नहीं करेगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई अन्तरण शून्य होगा।

(4) सोसाइटी द्वारा उधार दिए जाने के बाद उप-धारा (1) के अधीन सृजित भार भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 या ऋण उधार अधिनियम, 1884 के अधीन दिए गए उधार से उद्भूत सरकार के किसी दावे के विरुद्ध उपलब्ध होगा।

1883 का 19

1884 का 12

अध्याय-7

सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्ति और निधि

निधियों का निवेश। 53. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपनी निधियों का निम्नलिखित में निवेश या निक्षेप कर सकती :—

(क) डाकघर बचत बैंक में; या

(ख) भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में; या

1882 का 2

(ग) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अंशों या प्रतिभूतियों में; या

(घ) किसी बैंक या रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बैंक व्यापार चलाने के लिए अनुमोदित व्यक्ति के पास; या

(ङ) नियमों द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य रीति से।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किया गया कोई निवेश या निक्षेप, जो विधिमान्य होता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त होता, एतद्द्वारा अनुसमर्थित और पुष्ट किया जाता है।

सहकारी शिक्षा निधि में अभिदान। 54. सहकारी सोसाइटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से, लाभ के पांच प्रतिशत से अनधिक ऐसा प्रमाण, जो विहित किया जाए, नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा निधि में जमा करेगी।

निधियों का विभाजन न किया जाना। 55. सोसाइटी के लाभान्वित समानीकरण या बोनस समानीकरण निधियों से भिन्न निधियों या शुद्ध लाभों का भाग, इसके सदस्यों को बोनस या लाभान्वित के रूप में संदत्त या अन्यथा वितरित नहीं किया जाएगा :

परन्तु सदस्य को ऐसी मात्रा में जो उपविधियों द्वारा निर्धारित की जाए उस द्वारा की गई सोसाइटी को किन्हीं सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया जा सकेगा।

लाभों का विनियोजन। 56. (1) लाभ कमाने वाली सोसाइटी वर्ष के कुल लाभान्वितों में से अतिरिक्त लेखों पर प्रोद्भूत और प्रोद्भूत हो रहे सभी व्याज, स्थापना कार्य, उधारों और निक्षेपों पर संदेय व्याज, लेखा परीक्षा फीस, कार्यचालन खर्च, जिसके अन्तर्गत मुरम्मत, किराया, कर और अवमूल्यन

भी है, को घटा कर और डूबते ऋणों तथा हानियों को, जिनका लाभों से सुजित किसी निजि म प्रयाोज नहीं मिला गया है व्यवस्था करने या बट्टे खाने में डालने क पश्चात् शुद्ध लाभों की संगणना करेगी। सोसाइटी फिर भी वर्ष के शुद्ध लाभों में, पूर्वगामी वर्षों में प्रोदभूत किन्तु वास्तव में उस वर्ष के दौरान वसूल किए गए व्याज को जोड़ सकेगी। इस प्रकार निकाला गया लाभ, पूर्वगामी वर्ष के लाभों की राशि सहित विनियोजन के लिए उपलब्ध होगा।

(2) सोसाइटी अपने शुद्ध, लाभों को आरक्षित या किसी अन्य निधि में, सदस्यों को उनके अंशों पर लाभांश का संदाय करने, सोसाइटी को शिक्षा निधि में जो रजिस्ट्रार द्वारा इन निमित्त अधिसूचित की जाए, अभिदाय में, सदस्यों तथा व्यक्तियों जो इसके कारबार में सदस्य नहीं हैं से प्राप्त समर्थन के आधार पर बोनस के संदाय में, मानदेय, अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि पर और अन्य किसी प्रयोजन के लिए जो नियमों या उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए क प्रति विनियोजन कर सकेगी :

परन्तु सोसाइटी के इसकी वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदन और इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुरूप के विधाय, लाभों का कोई भाग विनियोजित नहीं किया जाएगा।

57. (1) प्रत्येक सोसाइटी अपने मध्यवहारों से व्युत्पन्न लाभों, यदि कोई हो, के बारे में एक आरक्षित निधि रखेगी।

आरक्षित निधि।

(2) प्रत्येक वर्ष में सोसाइटी के शुद्ध लाभों में से जो उसके पञ्चीस प्रतिशत से कम न हो या ऐसा उच्चतम अंश को ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लिए विहित किया जाए, को आरक्षित निधि में रखा जाएगा।

(3) ऐसी सीमा के सिवाय, और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इसके आरक्षित निधि का कोई भी भाग किसी सोसाइटी के कारबार में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(4) नियमों के अधीन रहत हुए, आरक्षित निधि का कोई प्रभाग जो सोसाइटी के कारबार में प्रयुक्त नहीं किया गया है निम्नलिखित में निवेशित या निक्षिप्त किया जाएगा; —

(क) डाक घर बचत बैंक में; या

1882 का 2

(ख) भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 की धारा 20 में, उस धारा के खण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से अन्यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं भी प्रतिभूतियों में; या

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित अन्य किसी बैंक में।

58. (1) कोई भी सोसाइटी सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को या इसके अपने अंशों की प्रतिभूति पर, अथवा किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिभूति पर जो सदस्य नहीं है, उधार नहीं देगी :

ऋण देने की नीति का विनियमन।

परन्तु रजिस्ट्रार की विशेष स्वीकृति पर, एक सोसाइटी अन्य सोसाइटी को उधार दे सकेगा।

(2) पूर्वगामी उप-धारा में किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार द सकेगी।

(3) यदि, राज्य सरकार की राय में सोसाइटी या सम्बद्ध सोसाइटियों के हित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा किसी सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, धन राशि क उधार दिए जान को निशिद्ध, निर्बन्धित अथवा विनियमित कर सकेगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, सोसाइटी या सम्बद्ध सोसाइटियों की निधियों को उनके उद्देश्यों को अग्रसर करने में ऐसी निधियों के उपयुक्त उपयोग और उन्हें नियमों तथा उपविधियों में अधि-कथित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय बैंक के परामर्श से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अतिरिक्त परिमाण, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा अपने सदस्यों या अन्य सोसाइटियों को उधार दिए जाने के परिमाण शर्त और रीति को आगे विनियमित कर सकेगा।

उधारों पर 59. सहकारी सोसाइटी केवल उस परिमाण तक और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित निबन्धन। की जाए या जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए, निक्षेप और उधार प्राप्त करेगी।

गैर सदस्यों 60. धारा 50 तथा 59 में उपबन्धित के सिवाय, सदस्य से भिन्न व्यक्ति के साथ क साथ सोसाइटी के संव्यवहार ऐसे निक्षेपों और निबन्धनों के यदि कोई हो, अधीन रखते हुए होंगे, अन्य संव्यव- जो विहित किए जाए। हारों पर निबन्धन।

अध्याय-8

लेखा परिक्षा, जांच, निरीक्षण और अधिभार

लेखा 61. (1) प्रत्येक सोसाइटी के लेखे को प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार और परीक्षा। ऐसी तारीख तक जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार या उस द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(2) लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, सोसाइटी ऐसी लेखा परीक्षा फीस यदि कोई हो, और ऐसी समय सीमा के भीतर, जो विहित की जाए संदत्त करेगी।

(3) यदि, लेखा परीक्षा के समय, सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं, तो रजिस्ट्रार या उप-धारा (1) के अधीन उस द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, लेखे को सोसाइटी के व्यय पर लिखवा सकेगा।

(4) किसी सोसाइटी से संदेय लेखा परीक्षा फीस, यदि कोई है, या सोसाइटी के लेखे लिखवाने के लिए उपगत व्यय धारा 90 में उपबन्धित रीति में वसूलीय होगा।

लेखा परी- 62. (1) धारा 61 के अधीन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

क्षा का स्वरूप।

- (क) नकद अतिशेषों, प्रतिभूतियों और स्टाकों का सत्यापन ;
- (ख) जापानाओं और लेनदारों के खातों में अतिशेष का और सोसाइटी के ऋणियों से देय राशियों का सत्यापन ;
- (ग) अति देय ऋणों, यदि कोई हो, की परीक्षा ;
- (घ) सोसाइटी की वास्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन ;
- (ङ) सोसाइटी के संव्यवहारों जिसके अन्तर्गत धन सम्बन्धी संव्यवहार भी ह, की परीक्षा ;
- (च) लेखों की विवरणी, जो प्रबन्धक सभिति द्वारा ऐसे प्ररूप में जो विहित किए जाए, तैयार की जाएगी, की परीक्षा ;
- (छ) प्राप्त लाभों का प्रमाण पत्र ; और
- (ज) अन्य कोई मामला जो विहित किया जाए।

(2) इस प्रकार लेखा परीक्षित लेखों की विवरणी, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसमें किए गए परिवर्तनों सहित, यदि कोई हों, अन्तिम और सहकारी सोसाइटी पर आबद्ध कर होगी।

63. लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा की समाप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर सहकारी सोसाइटी और रजिस्ट्रार को, परीक्षित लेखों की विवरणी सहित, एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित होगा, प्रस्तुत करेगा; —

लेखा परीक्षा की रिपोर्ट।

- (क) प्रत्येक व्यवहार जो उसे विधि या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत हो
- (ख) प्रत्येक धनराशि जो लेखों में लानी चाहिए थी किन्तु लाई नहीं गई है;
- (ग) किसी कमी या हानि की राशि जो किसी उपेक्षा या अव्यवहार के कारण हुई प्रतीत होती है, अथवा जिसकी आगे जांच पड़ताल अपेक्षित है;
- (घ) सोसाइटी की कोई राशि या सम्पत्ति जो, किसी व्यक्ति द्वारा द्विविनियोजित अथवा कपटपूर्वक प्रत्यक्षित की गई प्रतीत होती है;
- (ङ) प्राप्ति में से कोई जो उसको बकार या संदिग्ध प्रतीत होती है;
- (च) विहित किया गया अन्य कोई मामला।

64. सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रार द्वारा किन्हीं त्रुटियों या अनियमितताओं का जो लेखा परीक्षक द्वारा इंगित की गई हो, स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा, और तत्पश्चात् सोसाइटी ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति में, जो रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करें, ऐसी त्रुटियों और अनियमितताओं को सुधारेगी और उन पर इसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देगी।

त्रुटियों का परिशोधन।

65. रजिस्ट्रार समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का स्वयं निरीक्षण कर सकेगा या इस निमित्त उसका द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसे निरीक्षण की समाप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सोसाइटी को अपने निरीक्षण के परिणाम से संसूचित करेगा।

सहकारी सोसाइटीयों का निरीक्षण।

66. (1) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सोसाइटी के लेनदार के आवेदन पत्र पर, रजिस्ट्रार द्वारा या उस द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण किया जाएगा।

ऋणी सहकारी सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण।

(2) ऐसा कोई निरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि,—

- (क) रजिस्ट्रार का, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समाधान नहीं हो जाता है कि अभिकथित ऋण उस समय देय राशि है और लेनदार ने उसके संदाय की मांग की है तथा युक्ति-युक्त समय के भीतर उसे समाधान प्राप्त नहीं है; और
- (ख) लेनदार रजिस्ट्रार के पास निरीक्षण के वजय के लिए प्रतिभूति की ऐसी धनराशि जमा नहीं करता है जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित की जाए।

(3) इस धारा के अधीन निरीक्षण के परिणाम को रजिस्ट्रार लेनदार, सोसाइटी और वित्तीय बैंक को, यदि कोई हो, जिसकी सोसाइटी सदस्य है, संसूचित करेगा।

रजिस्ट्रार द्वारा जांच। 67. (1) रजिस्ट्रार, स्वचेरणा पर स्वयं या अपने लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच कर सकेगा।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की जांच निम्नलिखित के आवेदन पर की जाएगी :—

- (क) सोसाइटी, जिससे संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध है; या
- (ख) सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा; या
- (ग) सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्य द्वारा।

(3) रजिस्ट्रार या उप-धारा (1) के अधीन उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) वह, सोसाइटी की साधारण बैठक के लिए नोटिस की अवधि विनिर्दिष्ट करने वाले किसी नियम या उप-विधि के होते हुए भी, सोसाइटी या उसकी किसी शाखा के मुख्यालय में ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसे मामलों को अवधारित करने के लिए जो उस द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, साधारण बैठक बुलाने के लिए सोसाइटी के अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा और जहां सोसाइटी के अधिकारी बुलाने से इनकार करते हैं या इनमें अनफन रहते हैं, वहां उसे स्वयं इस बुलाने की शक्ति होगी; और
- (ख) खण्ड (क) के अधीन बुलाई गई किसी बैठक की, सोसाइटी की उप-विधियों के अधीन बुलाई गई साधारण बैठक की सभी शक्तियां होंगी और इसकी कार्यवाहियां ऐसी उप-विधियों द्वारा विनियमित की जाएंगी सिवाय इसके कि ऐसी बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) जहां इस धारा के अधीन जांच की जाती है, वहां रजिस्ट्रार जांच के परिणाम सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, यदि कोई है, जिससे वह सोसाइटी सम्बद्ध है और व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, यदि कोई है, जिनके अनुरोध पर जांच की जाती है संसूचित करेगा।

जांच का खर्च। 68. जहां धारा 67 के अधीन जांच की जाती है या धारा 66 के अधीन किसी लेनदार के आवेदन पर कोई निरीक्षण किया जाता है, वहां रजिस्ट्रार, खर्च या खर्च का ऐसा भाग, जैसा वह उचित समझे, सहकारी सोसाइटी जिससे सम्बन्धित सोसाइटी सम्बद्ध है, सोसाइटी, जांच या निरीक्षण की मांग करने वाले सदस्यों या लेनदारों और सोसाइटी के अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों के बीच प्रभाजित कर सकेगा परन्तु :—

- (क) इस धारा के अधीन खर्च के प्रभाजन का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक तद्धीन खर्च देने के लिए दायी बनाई जाने वाली सोसाइटी या व्यक्ति को मुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं द दिया जाता है;
- (ख) रजिस्ट्रार उन प्रधानों का, जिन पर खर्च प्रभावित किया है, लिखित रूप में कथन करेगा।

अधिवार। 69. (1) यदि सहकारी सोसाइटी को लेखा परीक्षा, जांच निरीक्षण या परिसमापन के दौरान, यह पता जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे ऐसी सोसाइटी का गठन या प्रबन्ध सौंपा गया है या सौंपा गया था अथवा जो किसी समय सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है या किसी समय रहा है अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के प्रतिकूल कोई संदाय किया है या उसने न्यास द्वारा भंग या जानबूझकर उपेक्षा द्वारा सोसाइटी की मास्तियों में किसी प्रकार की कमी की है या ऐसी सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या

कंपटन्तापूर्वक प्रतिधारित की, तो रजिस्ट्रार स्वयंरेण पर या समिति, समापक या किसी लेनदार के आवदन पर, ऐसे व्यक्ति के आचरण को स्वयं जांच कर सकता या अपने निश्चित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु इन उप-धारा में निर्दिष्ट किसी कार्य या लेन करने की जानकारी की तारीख से छह वर्षों के अवसान के पश्चात् ऐसी कोई जांच नहीं की जाएगी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई जांच की जाती है, वहां रजिस्ट्रार सम्बन्धित व्यक्ति को सूचनाई का अवसर देने के पश्चात् उससे धन या सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को ब्याज सहित ऐसी दर पर प्रतिसंदत्त करने या प्रत्यावर्तित करने, या उस परिमाण तक अभिदाय और खर्च या प्रतिफल संदत्त करने की अपेक्षा करने का आदेश कर सकेगा, जो रजिस्ट्रार न्याय संगत और साम्प्रपूर्ण समझे।

(3) यह धारा इस बात के होते हुए भी लागू होगी कि कार्य ऐसा है जिसके लिए अपराधी अपराधिक रूप में उत्तरदायी है।

70. रजिस्ट्रार और विहित निबन्धनों के अधीन रहते हुए, संपरीक्षक मध्यमस्थ, ग्रथवा पर्यवेक्षण या निरीक्षण अथवा संपरीक्षा या जांच करने वाले व्यक्ति की सभी व्यक्ति-युक्त समर्थों पर सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में बहियों, लेखों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्ति तक पहुंच होगी।

दस्तावेजों तक पहुंच।

71. (1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों को करते हुए रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या धारा 73 के अधीन विवाद का विनिश्चय करने वाला कोई अन्य व्यक्ति और सहकारी समिति के समापक को या संपरीक्षक निरीक्षण या जांच करने के हकदार किसी व्यक्ति को, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी :-

सिविल न्यायालय की शक्तियां।

- (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना ;
- (ग) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत ; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कर्मस्थान जारी करना।

(2) शपथ पत्र की दशा में यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अधिकारी, किसी विवाद का विनिश्चय करने वाला मध्यस्थ या अन्य कोई व्यक्ति समापक, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

अध्याय-9

विवादों का निपटारा

72. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारखार के विषय में निम्नलिखित में विवाद उत्पन्न होता है :-

विवाद जो माध्यस्थता में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

- (क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच ; या

- (ख) सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति और सोसाइटी उसकी समिति या भूतपूर्व या वर्तमान कोई अधिकारी एजेंट या कर्मचारी अथवा समापक के बीच; या
- (ग) सोसाइटी या उसकी समिति और किसी भूतपूर्व समिति, किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी अथवा किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व एजेंट या भूतपूर्व कर्मचारी अथवा सोसाइटी के किसी भूतपूर्व मृत अधिकारी या मृत एजेंट अथवा मृत कर्मचारी के नाम निर्देशितों, वारिसों, या विधिक प्रतिनिधियों के बीच; या
- (घ) सोसाइटी और किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के बीच, सोसाइटी या अन्य सोसाइटी के समापक के बीच अथवा एक सोसाइटी के समापक और अन्य सोसाइटी के समापक के बीच; या

(ङ) सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य अथवा सदस्य से मिल व्यक्ति जिसे सोसाइटी द्वारा धारा 58 के अधीन उधार अनुदत्त किया गया है का प्रतिभू, चाहे ऐसा प्रतिभू सोसाइटी का सदस्य है या नहीं; तो ऐसे विवाद विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किए जाएंगे और किसी न्यायालय को ऐसे विवाद के बारे में कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार के विषय में निम्नलिखित विवाद समझे जाएंगे; अर्थात्:—

- (क) सदस्य या मृत सदस्य के नाम निर्देशितों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों से उसे देय किसी ऋण या मांग के लिए सोसाइटी का दावा, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की जाए या नहीं; या
- (ख) मूल ऋणी के विरुद्ध किसी प्रतिभू द्वारा कोई दावा जहां सोसाइटी ने प्रतिभू से मूल ऋणी की चूक के फलस्वरूप मूल ऋणी द्वारा उसे देय किसी ऋण या मांग के बारे में कोई राशि प्रतिभू से वसूल की है, चाहे ऐसा ऋण या ऐसी मांग स्वीकार की जाती है या नहीं; या
- (ग) सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कोई विवाद सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार के विषय में विवाद है या नहीं, तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

माध्यस्थम
के लिए
विवादों का
निर्देश।

73. (1) रजिस्ट्रार, धारा 72 के अधीन विवाद का निर्देश प्राप्त करने पर; —

- (क) विवाद का विनिश्चय स्वयं कर सकेगा; या
- (ख) निपटान के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति को अनारित कर सकेगा जिसमें सरकार द्वारा इन निमित्त शक्तियां विनिहित की गई हैं; या
- (ग) निपटान के लिए इसे मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनारित या उस उप-धारा के खण्ड (ग) के अधीन निर्दिष्ट किसी निदेश को वापस ले सकेगा और उसका विनिश्चय स्वयं कर सकेगा या उसे किसी अन्य मध्यस्थ को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार या अन्य कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, विवाद पर विनिश्चय लिखित रहने तक, ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जैसे वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

(4) रजिस्ट्रार या मध्यस्थ जिसे विवाद निर्दिष्ट किया जाता है, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यथास्थिति, अपना विनिश्चय या अधिनिर्णय देगा।

(5) जहाँ विनिश्चय या अधिनिर्णय पक्षकार की अनुपस्थिति में किया जाता है, वहाँ उक्त पक्षकार, यदि व्यक्ति हो तो, ऐसे विनिश्चय या अधिनिर्णय की तारीख से एक महीने के प्रन्दर ऐसे विनिश्चय या अधिनिर्णय को अपास्त करने का आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह रजिस्ट्रार या मध्यस्थ का समाधान करा देता है कि जब सामला सुनवाई के लिए पुकारा गया था उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था तो रजिस्ट्रार या मध्यस्थ, यथास्थिति, अपने विनिश्चय या अधिनिर्णय का अपास्त करने को आदेश करेगा।

74. जहाँ विवाद धारा-72 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया गया है या धारा-73 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन मध्यस्थम के लिए अन्तरित या निर्दिष्ट किया है, वहाँ, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उस व्यक्ति का जिसे ऐसे विवाद का विनिश्चय करने के लिए शक्तियाँ विनिहित की गई हैं, अथवा मध्यस्थ का, यदि जांच पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि ऐसे मध्यस्थ का कोई पक्षकार किसी अधिनिर्णय के निष्पादन को जो किया जाए, लिखित करने या बाधित करने के आशय से—

अधिनिर्णय से पूर्व कुर्की।

- (क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है ; या
- (ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से बाहर हटाने वाला है ;

वहाँ जब तक पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे दी जाती है, सशर्त कुर्की का निदेश कर सकेगा, और ऐसी कुर्की का वैषा हो प्रभाव होगा मानों कि यह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया गया है।

75. धारा-73 के अधीन मध्यस्थ का अधिनिर्णय या रजिस्ट्रार अथवा उस व्यक्ति का विनिश्चय जिसमें विवादों का विनिश्चयन करने की शक्ति विनिहित की गई है, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिनिर्णय को लमया।

76. सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के बारे में सोसाइटी या उसके अधिकारियों में से किसी के विरुद्ध कोई बाद तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वाद हतुक वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान और अनुतोष, जिसका वह दावा करता है, का कथन करने वाला लिखित नोटिस रजिस्ट्रार को दिए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो महीने समाप्त नहीं हो गए हों, और वाद पर में यह कथन भी होगा कि नोटिस इस प्रकार दिया या छोड़ा जा चुका है।

वादों में नोटिस आवश्यक।

77. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ सोसाइटी और इस लेनदार वा ऋण लेनदारों अथवा उनके किसी वर्ग के मध्य किसी समझौते या व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है, वहाँ रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा या किसी लेनदार द्वारा अथवा ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसके बारे में सभापक द्वारा परिसमापन आदेश पाश्ति किया गया है, विहित दृग से कोई आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, लेनदारों या लेनदारों के वर्ग की ऐसी रीति में बैठक बुलाने, आयोजित करने और संचालित करने का आदेश दे सकगा, जसी विहित की जाए।

रजिस्ट्रार को सोसाइटी और लेनदारों के बीच समझौते की मंजूरी की शक्ति।

(2) यदि यथास्थिति, लेनदारों या लेनदारों के वर्ग में संख्या का बहुमत जो सोसाइटी द्वारा लेनदारों को देय ऋणों के तीन चौथाई बावों का प्रतिनिधित्व करता है, बैठक में व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित है, किसी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत हो जाता है, तो समझौता या व्यवस्था, यदि रजिस्ट्रार द्वारा विहित रीति से प्रकाशन पर, स्वीकृत की है, यथास्थिति, सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग पर, और सोसाइटी पर भी या उस पर सोसाइटी जिसके बारे में परिशिष्ट 1111 आदेश पारित किया गया है, समापक पर और उन सभी व्यक्तियों पर जिन्हें धारा 80 के अधीन समापक द्वारा सोसाइटी की आस्तियों में अभिदाय करने की अपेक्षा की गई है या की जाए, आवद्धकर होगी।

अध्याय-10

सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन

सोसाइटी
के परि-
समापन के
लिए आ-
देश।

78. (1) रजिस्ट्रार, यदि नियम किसी मामले में ऐसा विहित करते हों, लिखित आदेश द्वारा, निर्देश कर सकेगा कि किसी सहकारी सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाएगा, यदि,—

- (क) धारा-65 या धारा-66 के अधीन किए गए निरीक्षण या धारा, 67 के अधीन की गई किसी जांच के पश्चात्; या
- (ख) इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई किसी विषय साधारण बैठक में सोसाइटी के उपस्थित तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर किए गए आवेदन पर; या
- (ग) रजिस्ट्रार की स्वप्रेरण पर उस सहकारी सोसाइटी की दशा में जिसमें :—

- (1) काम प्रारम्भ नहीं किया है; या
- (2) काम करना बन्द कर दिया है; या
- (3) जिसका एक हजार रुपये से अनधिक अंश पूंजी तथा सदस्यों का निक्षेप है; या
- (4) इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों में रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी किसी शर्त का पालन करना बन्द कर दिया है।

यह राय हो कि सोसाइटी का परिसमापन करना चाहिए।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति विहित रीति में सोसाइटी और वित्तीय बैंक को, यदि कोई है, जिसकी सोसाइटी सदस्य है, सूचित की जाएगी।

(3) आदेश निम्न लिखित स प्रभावी होगा :—

- (क) जहां धारा 93 के अधीन कोई अपील नहीं की जाती है, अपील करने के लिए अनुमत समय की समाप्ति पर; या
- (ख) जहां कोई अपील की जाती है, अपील प्राधिकारी द्वारा अपील रद्द किए जाने पर।

समापक की
निष्पत्ति।

79. (1) जहां रजिस्ट्रार ने धारा 78 के अधीन सोसाइटी के परिसमापन के लिए आदेश किया है, वहां वह, नियमों के अनुसार समापक नियुक्त कर सकेगा और उसे हटा सकेगा और उसके स्थान पर अन्य नियुक्त कर सकेगा तथा उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, यदि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, सोसाइटी के अंश धारकों में से आनुविधान द्वारा एक समापक समिति जो अधिक से अधिक सात और कम से कम तीन अंश धारकों से गठित होगी, समापक को परामर्श और सहायता देने के लिए नियुक्त कर सकेगा, और किसी भी समय समिति क किसी सदस्य या पूरी समिति को हटा सकेगा, और, यथास्थिति, उसके या इसके स्थान पर अन्य को नियुक्त कर सकेगा।

(3) समापक, नियुक्ति पर, सोसाइटी की सभी सम्पत्ति, चीज वस्तु और अनु-योज्य दावों को, जिसकी सोसाइटी अधिकारी है या अधिकारी प्रतीत होती है अपनी अभिरक्षा या नियन्त्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीज-वस्तु और दावों को हानि या क्षय अथवा नुकसान से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाएगा, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे।

(4) जहां धारा 93 के अधीन अपील की जाती है, वहां समापक अपील पर विनिश्चय के लम्बित रहने तक उप-धारा (3) में उल्लिखित सम्पत्ति, चीज-वस्तु और अनुयोज्य दावों की अभिरक्षा या नियन्त्रण रखेगा और उसे उस उप-धारा में निर्दिष्ट कार्यवाही करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

(5) जहां अपील में किसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश रद्द किया जाता है वहां सोसाइटी की सम्पत्ति, चीज-वस्तु और अनुयोज्य दावे सोसाइटी में पुनर्निहित हो जाएंगे।

80. (1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उस सोसाइटी की, सम्पूर्ण आस्तियां, जिसके बारे में परिसमापन आदेश किया गया है, धारा 79 के अधीन नियुक्त समापक में उस तारीख से जिसको आदेश प्रभावी होता है, निहित हो जाएंगी और समापक को कि वह ऐसी आस्तियां विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करने की शक्ति प्राप्त होगी।

समापक की शक्तियां।

(2) रजिस्ट्रार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, ऐसे समापक को निम्नलिखित के लिए भी शक्तियां प्राप्त होंगी।

- (क) सोसाइटी की ओर से आने पदनाम से बाद और अन्य विधिक कार्य-वाहियां संस्थित करना और उनका प्रतिवाद करना ;
- (ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा अथवा सम्पदा द्वारा, या भूतपूर्व सदस्यों के नाम निर्देशितियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की आस्तियों में किए जाने वाले या किए जाने के लिए बकाया अभिदाय (जिसे अन्तर्गत दाय ऋण भी है) का समय-समय पर प्रबंधारण करना ;
- (ग) सोसाइटी के विरुद्ध सभी दावों के सम्बन्ध में अन्वेषण करना और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दावेदारों के बीच उत्पन्न होने वाले प्राथमिकता के प्रश्नों का विनिश्चय करना ;
- (घ) सोसाइटी के विरुद्ध दावों जिसके अन्तर्गत परिसमापन की तारीख तक व्याज भी है, उनकी अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, यदि कोई हों, सोसाइटी की आस्तियों के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः संदाय करना ; दावों के संदाय के पश्चात अधिशेष, यदि कोई हो, ऐसे परिसमापन आदेश की तारीख से उसके द्वारा नियत दर पर जो किसी भी दशा में संविदा दर से अधिक

- नहीं होगा, ब्याज के संदाय में लगाया जाएगा ;
- (ड) समापन खर्च की गणना करना और वह अवधारित करना कि उसका किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में वहन किया जाएगा ;
- (ध) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति, सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का नाम निवृत्ति है ;
- (छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण और वितरण के विषय में ऐसे निर्देश देना जो सोसाइटी के कार्यकलाप के परिसमापन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ;
- (ज) सोसाइटी के कारबार को वहाँ तक चलाना, जहाँ तक उसके लाभप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो ;
- (झ) लम्बेदारों या लम्बेदार होने का दावा करने वाले या वर्तमान या भावी कोई दावा रखने वाले अथवा रखने का अभिकथन करने वाले व्यक्तियों के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करना, जिस द्वारा सोसाइटी दायी बन सके ;
- (ञ) किसी व्यक्ति के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करना जिसके और सोसाइटी के मध्य कोई विवाद है और ऐसे किसी विवाद को माध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करना ;
- (ट) सोसाइटी के सदस्यों से परामर्श करने के पश्चात् सोसाइटी के विरुद्ध दावों का संदाय करने के बाद बचे अधिशेष का, यदि कोई हो, व्ययन करना ; और
- (ठ) सोसाइटी और सोसाइटी के किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी अथवा सोसाइटी के प्रति अपने दायित्व की आशंका रखने वाले व्यक्ति के बीच वर्तमान या भावी, निश्चित या संभावित, अस्तित्व में या अनुमित अस्तित्व में मांगों या मांगों के दायित्वों और ऋणों और ऋणों में परिणामिक होने योग्य दायित्वों, और सोसाइटी की आस्तियों या परिसमापन से किसी प्रकार सम्बन्धित या उनका प्रभावित करने वाले सभी प्रश्नों के बारे में ऐसे निर्बन्धनों पर जिन पर सहमति हो, समझौता करना और ऐसी किसी मांग, दायित्व, ऋण या दावे का उन्मोचन करने के लिए कोई प्रतिभूति लेना और उसके बारे में पूर्ण उन्मोचन करना ।

(3) इस द्वारा के अधीन समापक के आदेश के पश्चात् किया गया सम्पत्ति का कोई निजी अन्तरण या परिवर्तन, अथवा उस पर सृजित कोई विलगन या प्रभार परिसमापन के अधीन जहाँ तक सोसाइटी का सम्बन्ध है, अकृत और शून्य होगा ।

समापक द्वारा निर्धारित अभिदायों की प्राथमिकता ।

81. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 में किसी बात के होते हुए भी, समापक द्वारा निर्धारित अभिदाय, दिवालिया कार्यवाहियों में प्राथमिकता के क्रम, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को दम ऋणों के ठीक बाद का स्थान पाएगा ।

1920 का 5

समापक द्वारा बहियां जमा कराना और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

82. जब सोसाइटी के कार्यकलापों का परिसमापन कर दिया हो, तब समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा और सोसाइटी के अभिलेखों को ऐसे स्थान पर जमा करेगा जहाँ रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करे ।

83. (1) रजिस्ट्रार सोसाइटी के परिणामों का आदेश किसी भी दशा में रद्द कर सकता जहाँ उनकी राय में, सोसाइटी बनी रहनी चाहिए।

रजिस्ट्रार की सहकारी सोसाइटी के परिणामों पर आदेश या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति।

(2) किसी अन्य दशा में रजिस्ट्रार, सहायक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश करेगा।

84. इस अधिनियम में जैसा अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित है, उसके सिवाय, कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी के परिणामों या विघटन से सम्बन्धित किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेगा और जब परिणामों या आदेश कर दिया गया हो, तब सिवाय रजिस्ट्रार की स्वीकृति के और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, सोसाइटी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी या चलाई नहीं जाएगी।

परिणामों और विघटन मामलों में वाद का वर्जन।

85. रद्द की गई सोसाइटी की समादत्त शेष पूंजी सहित, सभी दावित्वों को पूरा करने के पश्चात् अधिशेष आस्तियाँ इसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जाएंगी किन्तु वे सोसाइटी की उप-विधियों में वर्णित किसी उद्देश्य या उद्देश्यों में और जब कोई अधिशेष वर्णित नहीं हो तो सोसाइटी की साधारण बैठक द्वारा अवधारित लोक उपयोगी किसी उद्देश्य में लगाई जाएंगी और विहित समय के अन्दर पूर्वोक्त उद्देश्य को अवधारित करने में साधारण बैठक को अतफलता की दशा में उन्हें, रजिस्ट्रार द्वारा, या तात्पूरणतः या अंशतः निम्नलिखित में से किसी या सभी के लिए समनुदेशित किया जा सकेगा :—

अधिशेष आस्तियों का व्ययन।

- (क) सहकारी शिक्षा निधि सहित स्थानीय हित का कोई लोकोपयोगी उद्देश्य ;
- (ख) पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 की धारा 2 में यथा परिभाषित कोई पूर्व प्रयोजन ;
- (ग) वित्तीय बक को ऐसे समय तक जब तक कि समान उद्देश्य वाली नई सोसाइटी उसी या पड़ोस के क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है, और जब रजिस्ट्रार की स्वीकृति से ऐसे अधिशेष ऐसी नई सोसाइटी को आरक्षित निधि में जमा किए जा सकेंगे।

अध्याय-11

अधिनियमों, डिक्लरेशनों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

86. अध्याय 9 या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अधिनियम में उपबन्धित वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त सशक्त उसका कोई अधीनस्थ व्यक्ति, सोसाइटी के आवेदन पर, किसी सदस्य या भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण या बकाया मांग के, सम्पत्ति या उसमें किसी हित को जो धारा-52 के अधीन भारत के अधीन है विक्रय द्वारा, संदाय निदिष्ट करते हुए आदेश कर सकेगा ;

भारत का प्रवर्तन।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नाम निर्देशित, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को विहित रीति में नोटिस नहीं दे दिया जाता है।

सहकारी सोसाइटी के व्यक्तिक्रमी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने की वित्तीय शक्तियां। 86-क (1) यदि कोई सहकारी सोसाइटी, इसके सदस्यों द्वारा देय धन के संदाय में व्यक्तिक्रम करने के कारण, इस धारा के कठार के निबंधनों के अनुसार अपने ऋणों का वित्तीय बैंक को संदाय करने में असमर्थ है, तो वित्तीय बैंक ऐसी सोसाइटी की समिति को, इस अधिनियम की धारा 72, धारा 73, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 86, धारा 87, धारा 89, धारा 90 और धारा 90-क के अधीन कार्यवाही करके ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगा।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की समिति, वित्तीय बैंक से ऐसा निर्देश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के अन्दर अपने व्यक्तिक्रम करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहती है, तो वित्तीय बैंक स्वयं ऐसा व्यक्तिक्रम करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा और उस दशा में अधिनियम की धारा 72, धारा 73, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 86, धारा 87, धारा 89, धारा 90 और धारा 90-क और तदधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के उपबंध ऐसे लागू होंगे, मानी अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के उक्त उपबंधों में सोसाइटी या इसके सदस्यों के प्रति निर्देश, वित्तीय बैंक के प्रति निर्देश हों।

(3) ऐसे सोसाइटी के व्यक्तिक्रम करने वाले सदस्यों से वसूली के पश्चात्, सोसाइटी में ऐसे सदस्यों से संबंधित लेखे और बैंक में सोसाइटी के लेखे क्रमशः सोसाइटी और बैंक द्वारा अनुपाततः जना किए जाएंगे।

वित्तीय बैंक को सोसाइटी के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां। 86-ख. जहां वित्तीय बैंक द्वारा सोसाइटी से इसे देय धन के बारे में सोसाइटी के विरुद्ध डिक्री या अधिनिर्णय अभिप्राप्त किया हो, वहां बैंक प्रथमतः सोसाइटी की उपलब्ध आस्तियों से और उसके पश्चात् उन द्वारा सोसाइटी की देय ऋणों की सीमा तक सोसाइटी के सदस्यों से वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा।

परन्तु वित्तीय बैंक इस धारा के अधीन सोसाइटी के ऐसे ऋणी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय, सोसाइटी की उपलब्ध आस्तियों से अनुष्ठ रहने वाली राशि की वसूली के लिए प्रथमतः सोसाइटी के व्यक्तिक्रम करने वाले सदस्यों और प्रतिभूतों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

आदेशों का निष्पादन। 87. (1) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 69 के अधीन या धारा-86 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, धारा 93 या 94 के अधीन किया प्रत्येक विनिश्चय या अधिनिर्णय और धारा 93 या 94 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यदि कार्यन्वित नहीं किया जाता है, तो यह भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार और नियमों के अधीन निष्पादित किया जाएगा।

परन्तु किसी धनराशि की वसूली के लिए आवेदन निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

(i) कलक्टर को और उससे रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र ; संलग्न किया जाएगा ;

(ii) आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय में निम्न तारीख से और यदि ऐसी तारीख नियत नहीं की गई हो तो आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय की तारीख से बारह वर्षों के भीतर।

(2) उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात्, सम्पत्ति का कोई निजी अन्तरण या परिदाय, अथवा उस पर सृजित ऋण भार या प्रभार, सोसाइटी के विरुद्ध जिनके आवेदन पर प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, अस्त और शून्य होगा।

88. धारा 80 के अधीन समापक के आदेश, भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अनुसार और नियमों के अधीन निष्पादित किए जाएंगे।

समापक के आदेशों का निष्पादन।

89. रजिस्ट्रार या उस द्वारा इन निमित्त मशकत कोई व्यक्ति, जब वह इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा या कुर्की के बिना सम्पत्ति के बिक्री द्वारा किसी राशि की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय अथवा ऐसी वसूली या ऐसी वसूली की सहायता में कोई कदम उठाने के लिए उसे किए गए किसी आवेदन पर आदेश करत समय, परिसीमा अधिनियम, 1963 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए विधिवि न्यायालय होगा।

रजिस्ट्रार या उसके द्वारा मशकत व्यक्ति का कुछ प्रयोजनों के लिए विधिवि न्यायालय होना।

90. (1) सहकारी सोसाइटी से या सोसाइटी के अधिकारी या सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य से ऐसे मदरा के रूप में सरकार को दिये सभी राशियाँ, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्ध के अधीन सरकार के पक्ष में अधिनियमित कोई खर्च भी है, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए प्रमाणपत्र पर उसी रीति में वसूल की जाएंगी जिनमें भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

सरकार को दिये राशियों की वसूली।

(2) सोसाइटी द्वारा सरकार को दिये और उप-धारा (1) के अधीन वसूलीय धनराशियाँ, प्रथमतः सोसाइटी की सम्पत्ति से; द्वितीयतः ऐसी सोसाइटी की दशा में जिस के सदस्यों का दायित्व परिसीमित है, उनके दायित्व की सीमा के अधीन रहते हुए सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से अथवा मृत सदस्यों से; और तृतीय, अन्य सोसाइटियों की दशा में सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की संपदाओं से वसूल की जा सकेगी।

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की सम्पदाओं का दायित्व सभी दशाओं में धारा 29 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होगा।

90-क धारा 72 या धारा 73 या धारा 87 में किसी बात के होते हुए भी, वित्तपोषण या मौसमी कृषि के वित्तपोषण का भार अपने ऊपर लेने वाली सहकारी सोसाइटी, फसलों के वित्तपोषण या मौसमी कृषि के वित्तपोषण के कारण सोसाइटी द्वारा अपने किन्हीं सदस्यों को अग्रिम के रूप में दी गई किसी धनराशि की बकाया की वसूली के लिए, रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगी, और ऐसे आवेदन के साथ ऐसे बकायों के बारे में लेखों का विवरण संलग्न करेगी।

फसल ऋण की वसूली।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर रजिस्ट्रार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और सम्बन्धित सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के

पश्चात्, उसके कथित देय ऐसे बकाया की राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र दे सकेगा।

(3) जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि सहकारी सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन अपने किसी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रही है, वहां रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और सम्बन्धित सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र दे सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र उसमें देय बकायों का अन्तिम और निश्चायक सबूत होगा और व भू-राजस्व की बकायों की वसूली के लिए तत्काल प्रवृत्त विधि के अनुसार वसूलीय होंगे।

स्पष्टीकरण:—

इस धारा के प्रयोजन के लिए पद :

(क) "फसलों का वित्तपोषण" से, जुताई मौसम के दौरान फसल उगाने या बाढ़ में जुताई के लिए, बोने, सृजना फेरने, निराई, कटाई करने, बीजों, या खाद खरीदने के लिए या कृषि सम्बन्धी अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, के लिए अग्रिम ऋण देना अभिप्रेत है और ऐसे ऋण उन फसलों की कटाई पर मौसम के दौरान प्रतिसंदेय हैं जिनके लिए ये अग्रिम रूप में दिए गए थे।

(ख) "मौसमी कृषिवित्त" से ऐसे कृषि प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं अग्रिम रूप में ऋण देना अभिप्रेत है और ऐसे ऋण ऐसी तारीख को या उससे पहले प्रतिसंदेय हैं, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं और विन्न-विन्न ऋणों के लिए विन्न-विन्न तारीखें विहित की जा सकेंगी।

अध्याय-12

अधिकारिता, अपील तथा पुनरीक्षण

परिचालन।

91. इस अधिनियम के अधीन सम्भावपूर्वक की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार के आधार पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

न्यायाधीशों
को प्रवि
कठिनाया
वर्जन।

92. (1) इस अधिनियम के उपबन्धित के विवाय किसी भी निविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी,—

- (क) सहकारी सोसाइटी का या उसकी उप-विधियों या इसकी उप-विधियों में किसी संशोधन का रजिस्ट्रीकरण ;
- (ख) समिति का हटाया जाना ;
- (ग) धारा-72 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित कोई विवाद ; और
- (घ) सोसाइटी के परिमर्मान और विवटन में सम्बन्धित कोई विषय।

(2) जब किसी सहकारी सोसाइटी का परिणामाप्त किया जा रहा है, तब सिवाय रजिस्ट्रार की अनुमति के और ऐसे निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करें, ऐसे समापक के विरुद्ध या सोसाइटी या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध एसी सोसाइटी के कारबार से सम्बन्धित कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही चलाई या संस्थित नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम में उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय की किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

93. (1) इस धारा के अधीन निम्नलिखित के विरुद्ध अपील होगी,—

अपील।

- (क) धारा 8 की उप-धारा (4) के अधीन किया गया रजिस्ट्रार का सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने का आदेश ;
- (ख) धारा 11 की उप-धारा (4) के अधीन किया गया रजिस्ट्रार का सोसाइटी की उप-विधियों से संशोधन को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने का आदेश ;
- (ग) सोसाइटी का, किसी व्यक्ति को, जो सोसाइटी की उप-विधियों के अधीन सदस्यता के लिए अन्यथा सम्यक् रूप से अर्हित है, सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित करने से इन्कार करने का विनिश्चय ;
- (घ) सोसाइटी का अपने किसी सदस्य को निष्कासित करने का विनिश्चय ;
- (ङ) धारा-37 के अधीन सहकारी सोसाइटी की समिति को हटाने के लिए किया गया रजिस्ट्रार का आदेश ;
- (च) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 67 के अधीन की गई जाव या धारा 66 के अधीन किए गए निरीक्षण की लागत को प्रभावित करने के लिए धारा 68 के अधीन किया गया आदेश ;
- (छ) प्रभार का, धारा 69 के अधीन, कोई आदेश ;
- (ज) धारा-73 के अधीन किया गया कोई विनिश्चय या अधिनिर्णय ;
- (झ) सहकारी सोसाइटी के समापन के लिए धारा 78 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया आदेश ;
- (ञ) धारा-80 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सोसाइटी के समापक द्वारा किया गया कोई आदेश ;
- (ट) धारा-74 के अधीन किया गया कोई आदेश ;
- (ठ) धारा 11-क की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया आदेश ;

या

- (ड) धारा 14-क की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया आदेश।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील,—

- (क) यदि विनिश्चय या आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया गया था, तो सरकार को ;
- या
- (ख) यदि विनिश्चय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो रजिस्ट्रार को ;

विनिश्चय या आदेश की तारीख से आठ दिन के अन्दर की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा अपील में किए गए किसी विनिश्चय पर आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी।

पुनर्विलो-
कन और
पुनरीक्षण।

94. (1) राज्य सरकार, सिवाय धारा 93 के अधीन की गई अपील के, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच या निरीक्षण या रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ अथवा उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख संग्रह करेगी और उनका परीक्षण कर सकेगी और उस पर ऐसे आदेश, जैसे वह उचित समझे, पारित कर सकेगी :

(2) रजिस्ट्रार किसी भी समय,—

(क) स्वयं उस द्वारा पारित किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी ;
या

(2) सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का नाम निर्देशित, वारिस या विधिक प्रतिनिधि जो किसी सम्पत्ति का ब्ययन करके जिसके बारे में सोसाइटी उस धारा के अधीन प्रथम भार रखने की हकदार है धारा 47 और 52 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या कोई ऐसा अन्य कार्य करता है जिससे ऐसे दावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी अथवा सदस्य, जो जब जानबूझकर निष्ठा विवरणी तैयार करता है या मिथ्या सूचना देता है, अथवा कोई व्यक्ति जो जानबूझकर या बिना युक्तियुक्त प्रति हेतु के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए किसी सम्पत्ति, अध्यापिका या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस निमित्त प्राबिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आपेक्षित कोई सूचना जानबूझ कर देता है, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) कोई निरोधक जो पर्याप्त हेतु के बिना, धारा-46 के अधीन उस द्वारा काटी गई राशि का सोसाइटी को एसी कटौती की तारीख से चौदह दिन की अवधि के अन्दर, संदाय करने में असफल रहता है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधिक अधीन किसी कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) कोई अधिकारी या अभिरक्षक धारा-38, धारा-70, और धारा-79 के अधीन हकदार व्यक्ति को सोसाइटी को, जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है, बहियों अभिलेख, नगदी, प्रतिभूति और अन्य सम्पत्ति की अभिरक्षा सौंपने में जानबूझ कर असफल रहता है, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जारी रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग ऐसे प्रथम भंग के लिए दोषमिधि के पश्चात् जारी रहता है, पांच रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(6) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी सम्पत्ति का कपटपूर्वक अर्जन करता है या उसके अर्जन दुष्प्रेरित करता है जो धारा 47 और 52 के अधीन भार के अधीन है, जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच या किए गए निरीक्षण या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की कार्यवाहियों के अभिलेख संग्रह करेगी और उनका परीक्षण कर सकेगी और यदि

उसे यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगवाए गए किसी विनिश्चय, आदेश या अधिनियम या किन्हीं कार्यवाहियों की किसी कारण से परिवर्तित, निष्प्रभावित या उलटना चाहिए, तो वह इस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे :

परन्तु उप-धारा (1) और (2) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व यथास्थिति, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, ऐसे आदेश द्वारा सम्भावितः प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी/करेगा :

परन्तु यह और कि धारा (1) और धारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन, यथास्थिति, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किए जाने वाले आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ।

95. जहाँ धारा 93 के अधीन कोई अपील की जाती है या जहाँ सरकार या रजिस्ट्रार धारा-94 के अधीन किसी मामले के अभिलेख मंगवाता, वहाँ, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या सरकार अथवा रजिस्ट्रार न्याय के उद्देश्य की विफलता का निवारण करने के लिए अपील या पुनरीक्षण के विनिश्चय के लम्बित रहने तक, ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश, जिसके अन्तर्गत रोक आदेश भी है, कर सकेगा, जैसे प्राधिकारी या सरकार अथवा रजिस्ट्रार उचित समझे ।

अन्तर्वर्ती
आदेश ।

अध्याय-13

अपराध और शास्तियाँ

96. (1) सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति जो सरकार की स्वीकृति के बिना, किसी ऐसे नाम या पदनाम से, जिसमें 'सहकारी' या किसी भारतीय भाषा में समतुल्य, शब्द भाग है कारबार चलाता है, जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रथम भंग के लिए सिद्धदोष पाए जाने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहता है, पाँच रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अपराध ।

97. (1) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अपराध का
संज्ञान ।

898 का 5

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में किसी बात को होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध, उक्त संहिता के प्रयोजनों के लिए, असंज्ञेय समझा जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन, रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना और उस द्वारा या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित परिवाद के बिना, संस्थिति नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 13-क

बीमाकृत सहकारी बैंक

97. (क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकृत बैंक की दशा में :—

बीमाकृत
सहकारी
बैंक के
परिसमापन
का आदेश ।

(i) बैंक क परिसमापन का अंश या समझौते अथवा ठहराव या समापन अथवा बैंक के पुनर्निर्माण जिसके अन्तर्गत विभाजन और पुनर्गठन भी है) की

स्वीकृत मंजूर करने का आदेश, केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी से ही किया जा सकता ;

- (ii) बैंक के परिममाणन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, यदि निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 13-घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में ऐसा करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित हो ;
- (iii) लोक हित में या जमाकर्ताओं के हित के लिए अहितकार रीति से बैंक के कार्यकलापों के संचालन को निवारित करने के लिए अथवा बैंक के प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो (ता बैंक की प्रबन्ध समिति या अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे उसका नाम जो भी हो) के अतिक्रमण (हटाए जाने) और उसके प्रशासक की नियुक्ति का ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो, जैसी समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा, और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक, उसकी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे बैंक की नई समिति की प्रथम बैठक की तारीख से ठीक पूर्व के दिन तक, पद पर बना रहेगा ;
- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी से या अपेक्षा पर किए गए, खण्ड (i), (ii), या (iii) में यथा निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध, कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और इस प्रकार मंजूर किया गया आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।
- (v) यथास्थिति, समापक या बीमा कृत सहकारी बैंक अथवा अंतरिति बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम को, अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों, सीमा और रीति में प्रतिसंदाय करने की बाध्यता के अधीन होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

- (i) "सहकारी बैंक" से निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित बैंक अभिप्रेत है ;
- (ii) "बीमाकृत सहकारी बैंक" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधीन एक बीमाकृत बैंक है ;
- (iii) "अंतरिति बैंक" से बीमाकृत बैंक के संबंध में एक ऐसा सहकारी बैंक से अभिप्रेत है :—

- (क) जिसके साथ ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक समामेलित किया जाता है ; या
- (ख) जिसको ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक की आस्थियां अन्तर्लिखित की जाती है ; या
- (ग) जिसमें धारा 14 के उपबन्धों के अधीन ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक में विभाजित या संपरिवर्तित किया जाता है ।

अध्याय-14

प्रकीर्ण

98. (1) हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी परिषद के नाम से एक परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः—

- (i) राज्य में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित मंत्री, पदनाम चाहे जो भी हों ;

राज्य सह-
कारी परि-
षद् का
गठन, इसके
कृत्य आदि ।

- (ii) शिखर सोसाइटियों का अध्याक्ष ;
- (iii) पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनमें से एक औरत, एक जाति अनुसूचित जाति का तथा एक व्यक्ति अनुसूचित जन जाति का होगा ;
- (iv) तीन सदस्य जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने मस चुने जाएंगे ;
- (v) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विभाग का सरकार का सचिव ;
- (vi) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ हिमाचल प्रदेश ;
- (vii) निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश; और
- (viii) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश।

(ख) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री, परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(ग) राज्य मंत्री, यदि वह खण्ड (ख) के अधीन परिषद् का अध्यक्ष नहीं है या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित कोई ऐसा राज्य मंत्री नहीं है, तो सहकारी सोसाइटियों के विभाग का उप मंत्री परिषद् का उपाध्यक्ष होगा।

परन्तु यदि सहकारी सोसाइटी से संबंधित कोई ऐसा राज्य मंत्री या उपमंत्री उपाध्यक्ष बनाए जाने के लिए नहीं है, या यथ स्थिति, ऐसा राज्य मंत्री या उपमंत्री, खण्ड (ख) के अधीन अध्यक्ष है तो परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से उपाध्यक्ष चुना जाएगा।

(2) ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) इस प्रकार गठित परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

- (क) सहकारी आन्दोलन से सम्बद्ध सभी साधन्य प्रश्नों पर राज्य सरकार को परामर्श देना ;
- (ख) सहकारी आन्दोलन का पुनर्विलोकन करना और राज्य में सहकारी सोसाइटियों के कार्यकांशों के समन्वय के तरीकों के बारे में सुझाव देना ;
- (ग) राज्य में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अपने प्रशासन में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए अर्थोपायों के बारे में सुझाव देना ;
- (घ) सहकारी सोसाइटियों के प्रशासन से सम्बन्धित किसी मामले के बारे में राज्य सरकार को स्वप्रेरणा से सिफारिश करना ; और
- (ङ) राज्य सरकार को ऐसे मामलों पर जो इसे राज्य सरकार द्वारा इसकी राय के लिए निदिष्ट किए जाएं, रिपोर्ट देना।

(4) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकती :—

- (क) परिषद् की बैठक बुलाने और बैठक में प्रक्रिया ;
- (ख) परिषद् के प्रति सचिव के कर्तव्य ;
- (ग) परिषद् की उप-समितियाँ ;
- (घ) परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि और परिषद् के सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता।

सहकारी
शब्द के
प्रयोग पर
प्रतिशोध।

99. सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी ऐसे नाम या पदनाम से, "सहकारी शब्द" या किसी भारतीय भाषा का समतुल्य शब्द जिसका भाग है, व्यवसाय नहीं करेगा या कारबार नहीं चलायेगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति या उसके हित उत्तराधिकारी द्वारा किसी ऐसे नाम या पदनाम के प्रयोग पर लागू नहीं होगी, जिसके अधीन वह उस तारीख को कारबार कर रहा था, जिसको, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 प्रवर्तन में 1912 का 2 आया।

इस अधि-
नियम के
उपबन्धों से
सहकारी
सोसाइटियों
से छूट देने
की शक्ति।

100. राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा :—

- (क) किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के लागू होने से छूट दे सकेगी : और
- (ख) निर्देश दे सकेगी कि ऐसे कोई उपबन्ध ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को ऐसी सीमा तक लागू होंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।"

अधिनियम
के अधीन
नोटिस की
तामील।

101. इन अधिनियम के अधीन जारी किया गया या बनाया गया प्रत्येक नोटिस या आदेश को किसी व्यक्ति को देकर या इसे ऐसे व्यक्ति के अन्तिम ज्ञातव्य निवास या कारबार के स्थान का उचित रूप से पता लिखकर, पूर्व मंदत और रजिस्ट्रीकृत डाक पत्र द्वारा जिसमें नोटिस या आदेश रखा हो, भेज कर तामील किया जा सकेगा और जब तक प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, ऐसी तामील ऐसे समय पर की गई समझी जाएगी जब पत्र साधारण क्रम से वितरित किया जाता।

सहकारी
सोसाइटियों
के कार्यों का
कुछ त्रुटियों
के कारण
अविधिमन्य
न होना।

102. (1) सोसाइटी या प्रबन्धक समिति अथवा किसी अधिधारी या समापक का कोई कार्य जो सोसाइटी के कारबार के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक किया गया है, सोसाइटी के संगठन या प्रबन्ध समिति के संगठन या अधिधारी अथवा समापक की नियुक्ति या निर्वाचन में तत्पश्चात् पाई गई किसी त्रुटि के कारण अथवा इस आधार पर कि ऐसा अधिधारी या समापक नियुक्ति के लिए निरहित था, अविधिमन्य नहीं समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कोई भी कार्य केवल इस तथ्य के कारण कि उसकी नियुक्ति को इस अधिनियम के अधीन तत्पश्चात् पारित किसी आदेश द्वारा या उसके परिणाम स्वरूप रद्द कर दिया गया है, अविधिमन्य नहीं होगा।

(3) यह विनिश्चय रजिस्ट्रार करेगा कि क्या कोई कार्य सोसाइटी के कारबार के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया था।

कम्पनी
अधिनियम
का लागू
न होना।

103. कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे। 1956 का 1

राज्य से
बाहर सोसा-
इटियों की
शाखाएं
इत्यादि।

104. हिमाचल प्रदेश के बाहर रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सोसाइटी जिसकी हिमाचल प्रदेश के अन्दर कोई शाखा है या कोई शाखा अथवा कारबार का कोई स्थान स्थापित करती है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से या ऐसी शाखा या कारबार के स्थान की स्थापना से छः मास के अन्दर रजिस्ट्रार के पास उपाधियों और संशोधन की एक प्रमाणित प्रति दाखिल करेगी और रजिस्ट्रार को, उस राज्य के जहां वह रजिस्ट्रीकृत है रजिस्ट्रार को भेजी गई

विवरणियों और सूचना के प्रतिरिक्त, ऐसी विवरणियाँ और सूचना पोजेगी, जैसी कि हिमाचल प्रदेश में उस प्रकार की सोसाइटियों द्वारा भजी जाती है।

सहकारी कर्मचारी का 105. इस अधिनियम के अन्य किन्हीं उपबन्धों और नियमों में किसी बात के होते हुए भी यदि सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को सलाह देता है और उसकी उपस्थिति समिति के कार्यकृत में अभिलिखित की जाती है, तो समिति के अन्य सदस्यों के साथ-साथ ऐसा सरकारी कर्मचारी भी किसी ऐसी कार्यवाही के लिए जो उसकी सलाह पर लिए गए विनिश्चय के आधार पर या तो विभागीय तौर पर या किसी विधिन्यायालय में प्रारम्भ की जाती है, दायी ठहराया जाएगा।

निरसन। 106. प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में सभावित क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1956 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में 1966 का 31 यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 एतद्द्वारा निरसित किए 1961 का 25 जाते हैं।

विद्यमान 107. (1) इस समय विद्यमान प्रत्येक सोसाइटी जो, सहकारी प्रत्येक सोसाइटी अधिनियम, 1904 के अधीन, या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1956 के अधीन या पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1954 के अधीन या पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएगी और इसकी उपविधियाँ, जहाँ तक वे इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवर्तन में रहेंगी जब तक वे परिवर्तित या विखण्डित नहीं कर दी जाती।

(2) धारा 106 के अधीन निरसित किए गए किन्हीं भी अधिनियमों के अधीन की गई सभी नियुक्तियाँ, बनाए गए नियम या आदेश, जारी की गई सभी अधिसूचनाएँ और नोटिस किए गए सभी संबन्धवार और संस्थित किए गए सभी वाद तथा संस्थित की गई कार्यवाहियाँ, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हैं, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः की गई, जारी की गई, किए गए और संस्थित की गई समझी जाएगी।

सहकारी 108. राज्य सरकार निम्नों के अधीन यथाविहित सहकारी अपील अधिकरण की अपील प्राधिकरण नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकरण को सभी या किन्हीं अपीलीय या पुनरीक्षण की शक्तियों का, जिनका इस द्वारा धारा 93, धारा 94 और धारा 95 के अधीन प्रयोग किया जाता है, प्रत्यायोजन कर सकेगी।

अध्याय-15

नियम बनाने की शक्ति

नियम बनाने 109. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के की शक्ति। लिए, सम्पूर्ण राज्य या उसका किसी भाग के लिए और किसी सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटियों के वर्ग के लिए, पूर्व प्रकाशन क प्रस्ताव नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टताओं और पूर्वगामी शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगी, अर्थात्:—

- (क) आवेदक जिसे सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा भेजा जाए ;
- (ख) सहकारी सोसाइटी के दायित्व के स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया और शर्तें ;
- (ग) वे विषय जिनके बारे में सहकारी समिति उपविधियां बनाएंगी ;
- (घ) सोसाइटी द्वारा उप-विधियों में संशोधन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ङ) उन व्यक्तियों की अर्हताएं या निरर्हताएं जिनको सोसाइटियों के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा ;
- (च) सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक की, अन्य सोसाइटी जिसकी वह सदस्य है के किसी बैठक में प्रतिनिधित्व करने और अपनी ओर से मत देने के लिए नियुक्ति ;
- (छ) ऐसे व्यक्ति के नाम निर्देशन के लिए प्रक्रिया, जिसे किसी सदस्य के उसकी मृत्यु पर शेयर या हित अन्तर्हित किए जा सके या जिसको उनके मूल्य का संदाय किया जा सके ;
- (ज) वह रीति जिससे मृत सदस्य के शेयर का मूल्य अभिनिश्चित किया जाएगा ;
- (झ) साधारण बैठक बुनाने, इसकी गणपूर्ति और कार्यवृत्त लिखने की प्रक्रिया और अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;
- (ञ) महासभा की शक्तियां ;
- (ट) किन्हीं प्रणोदक ऋणों और आस्तियों को बट्टे खाते डालना ;
- (ठ) सोसाइटी के महानिर्वाह द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन ;
- (ड) सोसाइटी के साधारण बैठक के लिए सभापेक्षा करना ;
- (ढ) नई समितियों या रजिस्ट्रार द्वारा हटाई गई समिति के स्थान पर नियुक्त प्रशासकों को संदेय पारिश्रमिक ;
- (ण) सोसाइटी की समिति की सदस्यता के लिए अर्हताएं या निरर्हताएं ;
- (त) सोसाइटियों के कर्मचारियों की अर्हताएं ;
- (थ) सोसाइटियों के साथ संविदाओं में हितबद्ध सोसाइटी के कार्य कलापों के विरुद्ध प्रतिषेध ;
- (द) सहकारी सोसाइटियों में राज्य सरकार की सदस्यता से सम्बद्ध विषय ;
- (ध) दरजिन पर सोसाइटियों द्वारा लाभोपसंदाय किया जा सके ;
- (न) सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने शुद्ध लाभों में से सहकारी शिक्षा निधि को दिया जाने वाला संदाय और इसके निवेश की रीति ;
- (प) सोसाइटी की निधियों के निवेश की रीति ;
- (फ) सोसाइटी की आरक्षित निधि के उद्देश्य पर इसके निवेश ;
- (ब) सोसाइटी के परिसमापन पर इसकी आरक्षित निधि के व्ययन की रीति ;
- (भ) परिणाम और शर्तें जिनके अध्वयधीन सोसाइटी निक्षेपों तथा उधारों को वसूल कर सकती ;
- (म) सहकारी सोसाइटी द्वारा गैर सदस्यों के साथ संव्यवहारों पर निबन्धन ;
- (य) सोसाइटी द्वारा अपने शेयरों पर, उधार प्रदत्त करने पर निबन्धन ;
- (कक) सहकारी सोसाइटियों पर लेखा परीक्षा फीच उद्गृहीत करना ;
- (कख) रजिस्ट्रार मध्यस्थ या विवादों का विनिश्चय करने वाले अन्य व्यक्ति के कार्यवाहियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- (कग) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए सोसाइटी की अस्थियां समापक में निहित होंगी और सहकारी सोसाइटी के परिसमापन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (कघ) सहकारी सोसाइटी को देय या सदेय राशियों की वसूली की प्रक्रिया;
- (कङ) अधिनिर्णय से पूर्व कुर्की करने की रीति;
- (कच) सहकारी सोसाइटी के पते की रजिस्ट्रीकृत करने की रीति;
- (कछ) सहकारी सोसाइटी द्वारा रखे जाने वाली लेख बहियों और रजिस्टर और रजिस्ट्रार के लेखों और बहियों को अधिलिखित करने के निर्देश देने की शक्ति;
- (काज) सोसाइटी की बहियों में प्रविष्टियों को और अपन कारबार के क्रम में इस द्वारा रख गए दस्तावेजों की प्रतियों को प्रमाणित करने की रीति;
- (कक्ष) सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और रिपोर्ट;
- (काञ) विधि व्यवसायी के रूप में उपसजात होने वाले व्यक्तियों पर निर्बन्धन;
- (कट) दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां देने के लिए फीस का उद्ग्रहण;
- (कठ) धारा 54 के अधीन सहकारी शिक्षा निधि का गठन;
- (कड) इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुमत विषय;
- (कड़) धारा 98 के अधीन गठित परिषद से सम्बद्ध विषय;
- (कण) धारा 108 के अधीन नियुक्त किए गए अपील अधिकरण से सम्बद्ध विषय।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी नियम के बनाते समय, राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि उसे भंग करने वाला कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर जुर्माने से, जो पचास रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां भंग जारी रहने वाला हो। वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग, ऐसे भंग के लिए दाय सिद्ध के पश्चात् जारी रहता है, दन रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में से पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसका अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

